www.sanjanabharati.com
दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर से प्रकाशित। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व उत्तराखंड में प्रसारित
facebook.com/Sanjanabharati

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

संजना भारती

RNI No. : DELHIN/2016/70240

आपका भरोसा, हमारी ताकत

2 दूरगामी लाभ का निर्णय है जिलों की समाप्ति...
3 हड़ताल न होना सबसे बड़ी उपलब्धि-पुलिस कमिश्नर...
4 अपराध पर अंकुश लगाना होगी पहली प्राथमिकता...

वर्षः 9 | अंकः 67 | दिल्ली, मंगलवार, 31 दिसम्बर 2024 | पृष्ठ संख्याः 4 | मूल्यः 1 रुपया

सीमांत प्रौद्योगिकियों में निपुणता हासिल करना समय की मांग हैः राजनाथ सिंह

'एकीकरण और एकजुटता के माध्यम से सशस्त्र बल अधिक कुशलता से चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होंगे'

संजना भारती/पीआईबी

मध्य प्रदेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को मध्य प्रदेश के महू में आर्मी वॉर कॉलेज (एडब्ल्यूसी) में अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा झ आज के लगातार विकसित होते समय में सीमांत प्रौद्योगिकियों में महारत हासिल करना समय की मांग है और सैन्य प्रशिक्षण केंद्र हमारे सैनिकों को भविष्य की चुनौतियों का मुकाबला करने को महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। युद्ध के तरीकों में देखे जा रहे आमूल-चूल परिवर्तनों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि सूचना युद्ध, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित युद्ध, छद्म युद्ध, विद्युत-चुंबकीय युद्ध, अंतरिक्ष युद्ध और साइबर हमले जैसे गैर-परंपरागत तरीके आज के समय में बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। रक्षा मंत्री ने जोर दिया कि सेना को ऐसी चुनौतियों का मुकाबला करने को बेहतर तरीके से प्रशिक्षित और सुसज्जित रहना चाहिए। उन्होंने महू में प्रशिक्षण केंद्रों की इन प्रयासों में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए सराहना की। उन्होंने बदलते समय के साथ अपने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में लगातार सुधार करने और कर्मियों को हर तरह की चुनौती के लिए तैयार करने के प्रयासों के लिए केंद्रों की सराहना की। श्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के विजन पर प्रकाश डाला और वर्तमान समय को संक्रमण काल बताया। केंद्रीय मंत्री ने कहा-भारत निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है और तेजी से एक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है। सैन्य दृष्टि से हम आधुनिक हथियारों से लैस हो रहे हैं। हम दूसरे देशों को मेड-इन-इंडिया उपकरण भी निर्यात कर रहे हैं। हमारा रक्षा निर्यात, जो एक दशक पहले लगभग 2,000 करोड़ रुपये का था, आज 21,000 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड आंकड़े को पार कर गया है। हमने 2029 तक 50,000 करोड़ रुपये का निर्यात लक्ष्य रखा है। रक्षा मंत्री ने तीनों सेनाओं के बीच एकीकरण और एकजुटता को मजबूत करने के सरकार के संकल्प को दोहराया और विश्वास जताया कि आने वाले समय में सशस्त्र बल बेहतर और अधिक कुशल तरीके से चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होंगे। उन्होंने इस तथ्य की सराहना की कि महू छावनी में सभी विंग के अधिकारियों को उच्चस्तरीय प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्होंने अधिकारियों से इन्फैंट्री स्कूल में हथियार प्रशिक्षण; मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (एमसीटीई) में एआई और संचार प्रौद्योगिकी और एडब्ल्यूसी में जूनियर और सीनियर कमांड में नेतृत्व जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण के माध्यम से एकीकरण को बढ़ावा देने की संभावना तलाशने का आग्रह किया।

श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भविष्य में कुछ अधिकारी रक्षा अताशे के रूप में काम करेंगे और उन्हें वैश्विक स्तर पर राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। श्री सिंह ने कहा -"जब आप रक्षा अताशे का पद संभालेंगे, तो आपको सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण को आत्मसात करना चाहिए। आत्मनिर्भरता के माध्यम से ही भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत कर सकता है और विश्व मंच पर अधिक सम्मान हासिल कर सकता है।"

हमारा ध्यान नागरिक संतुष्टि पर भी होना चाहिएः डॉ. जितेंद्र सिंह

संजना भारती/पीआईबी

नई दिल्ली। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान तथा कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में आयोजित व्यापक वर्षांत समीक्षा में प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के तहत लोक शिकायत निवारण में किए गए परिवर्तनकारी उपायों का उल्लेख किया।

डॉ. सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दृष्टिकल्पना के अनुरूप संपूर्ण सरकार और संपूर्ण राष्ट्र के दृष्टिकोण को सम्मेलित करने का आह्वान किया जिसका उद्देश्य प्रभावी शासन प्रदान करना और नागरिक संतुष्टि बढ़ाना है। डॉ. सिंह ने ज्ञान भागीदार के रूप में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के साथ विकसित द्वितीय इंटेलिजेंट शिकायत निगरानी प्रणाली (आईजीएमएस) की उन्नत क्षमताओं का उल्लेख किया। इसमें केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली प्लेटफॉर्म पर शिकायत प्रबंधन में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) का इस्तेमाल किया गया है। पूवार्नुमानित विश्लेषण और प्रणालीगत अंतर्दृष्टि को सक्षम बनाकर इंटेलिजेंट शिकायत निगरानी प्रणाली 2- नागरिकों को बेहतर परिणाम सुनिश्चित करता है और उन्हें जानकारी द्वारा नीति हस्तक्षेप की सुविधा प्रदान करता है। प्रौद्योगिकी-संचालित सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता दशार्ते हुए डॉ. सिंह ने केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली में अगली पीढ़ी के सुधारों के लिए 270 करोड़ रूपए की सरकारी मंजूरी की घोषणा की। दुनिया के सबसे बड़े नागरिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म के रूप में केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली को उन्नत, बहुभाषी, शिकायत संबंधी अद्यतन जानकारी हासिल करने और कुशल प्रतिपुष्टि तंत्र से लैस किया गया है। इससे शिकायत निवारण समय में काफी कमी आई है। डॉ. सिंह ने कहा कि शिकायत सुलझाने के समय में उल्लेखनीय कमी आई है और अब यह घटकर केवल 12 दिन रह गया है।

ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केजरीवाल ने ठगा नहींः हरदीप सिंह पुरी

(एजेन्सी)।

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पार्टी की कल्याणकारी योजनाओं को लेकर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री पर लोगों को 'धोखा' देने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री ने कहा, "ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केजरीवाल ने ठगा नहीं।" पुरी ने दावा किया कि महिला 'सम्मान योजना' और 'संजीवनी' योजना में उचित बजटीय प्रावधानों और कैबिनेट की मंजूरी का अभाव है। महिला सम्मान योजना का उद्देश्य दिल्ली में रहने वाली महिलाओं को प्रति माह 2,100 रुपये प्रदान करना है।

मंत्री ने योजनाओं की ईमानदारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि स्पष्ट वित्तीय समर्थन या मजबूत कार्यान्वयन प्रक्रिया के बिना ऐसी योजनाओं की घोषणा करना लोगों के साथ विश्वासघात है। उन्होंने कहा कि आप योजनाएँ बना सकते हैं लेकिन इसके लिए बजटीय प्रावधान होना चाहिए। योजना को आगे भी बढ़ाना है। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब में महिलाओं से किए गए वादे पूरे नहीं किए गए और वह दिल्ली में महिलाओं को 2,100 रुपये देने की एक और योजना लेकर आए। क्या उनकी कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दी? क्या उन्होंने बजट का संचालन किया?

पुरी से सवाल किया कि वे योजना के इरादे की घोषणा कर सकते हैं लेकिन वे लोगों से फॉर्म भरवा रहे हैं, यह लोगों के साथ 'धोखा' है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर कोई उत्पाद ही नहीं है तो कोई उत्पाद कैसे बेच सकता है? केजरीवाल द्वारा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर उनके निर्वाचन क्षेत्र में "ऑपरेशन लोटस" चलाने का आरोप लगाने के बाद पुरी ने अरविंद केजरीवाल पर 'मानसिक संतुलन' खोने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि जब अरविंद केजरीवाल (जेल में) 'सरकारी आतिथ्य' में थे, तो उनका 'मानसिक संतुलन' गड़बड़ा गया...अरविंद केजरीवाल का दृष्टिकोण क्या है - विघटन?...अरविंद केजरीवाल के पास बहुत कम समय बचा है।

नवयुग सुरंग का नाम मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाना चाहिए : उमर अब्दुल्ला

जम्मू कश्मीर (एजेन्सी)। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रविवार को कहा कि इस केंद्र शासित प्रदेश के विकास में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के योगदान को देखते हुए कश्मीर को जम्मू क्षेत्र से जोड़ने वाली नवयुग सुरंग का नाम उनके (सिंह के) नाम पर रखा जाना चाहिए। अब्दुल्ला ने यहां संवाददाताओं से कहा, श्रीनगर-जम्मू राजमार्ग पर दो सुरंग हैं। एक का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। दूसरी सुरंग (नवयुग) का नाम मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंह ने जम्मू-कश्मीर के विकास एवं कल्याण के लिए जबरदस्त योगदान दिया था। सिंह का तीन दिन पहले निधन हो गया था।

'आप' सत्ता में लौटने पर ग्रंथियों और पुजारियों को 18,000 रुपये प्रतिमाह देगी : केजरीवाल

(एजेन्सी)।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को 18,000 रुपये मासिक भत्ता देने का वादा करते हुए सोमवार को घोषणा की कि अगर उनकी पार्टी दिल्ली में दोबारा सत्ता में आती है तो पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना शुरू की जाएगी।

यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब दिल्ली में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों में आप लगातार चौथी बार सत्ता में बने रहने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल ने कहा, पुजारी और ग्रंथी हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, लेकिन उनकी अक्सर उपेक्षा की जाती है। देश में पहली बार, हम उन्हें समर्थन देने के लिए एक योजना शुरू कर रहे हैं जिसके तहत उन्हें 18,000 रुपये का मासिक भत्ता दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए पंजीकरण कल यानी मंगलवार से शुरू होगा। उन्होंने यह भी कहा कि वह मंगलवार को कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर जाकर वहां पुजारियों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया का निरीक्षण करेंगे।

स्टॉप पर बस न रोकने वाले ड्राइवरों-कंडक्टरों पर होगी कारवाईः आतिशी

■ **अगर कोई बस अपने स्टॉप पर नहीं रुकती है तो महिलाएं उसका फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डालें**

संजना भारती/संजय कुमार

नई दिल्ली। दिल्ली के अंदर महिलाओं को देखकर बसें न रोकने वाले डीटीसी और क्लस्टर बसों के ड्राइवर और कंडक्टर की अब खैर नहीं है। "आप" सरकार ने इन बसों के ड्राइवर और कंडक्टर को सस्पेंड करने का आदेश जारी किया है। दरअसल, दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों से दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री आतिशी को महिलाएं शिकायत कर रही हैं कि निर्धारित स्टॉप पर उनको देखकर डीटीसी और क्लस्टर बसों के ड्राइवर नहीं रुकते हैं। इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए सीएम आतिशी ने यह आदेश दिया है। साथी ही, सीएम आतिशी ने महिलाओं से अपील की है कि अगर कोई बस अपने निर्धारित स्टॉप पर नहीं रुकती है तो महिलाएं उसकी फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल दें, उसके ड्राइवर और कंडक्टर के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा महिलाएं और बेटियां नौकरी व पढ़ाई के लिए बस से सफर करें। इसके लिए ही सरकार ने बस यात्रा मुफ़्त की हुई है।

दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने सोमवार को कहा कि दिल्ली सरकार को और मुझे व्यक्तिगत तौर पर दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों से महिलाओं की शिकायत आ रही थी कि जो डीटीसी और कलस्टर बसों के ड्राइवर और कंडक्टर हैं वह अक्सर महिलाओं को देखकर बस नहीं रोकते हैं। अगर किसी बस स्टॉप पर सिर्फ महिलाएं खड़ी होती हैं तो ड्राइवर बस नहीं रोकते हैं और बस चलाकर आगे निकल जाते हैं। दिल्ली के कई हिस्सों से यह शिकायत आई है। मैं सबसे पहले दिल्ली की महिलाओं को यह आश्वस्त करना चाहती हूं कि वह बसों में ज्यादा से ज्यादा संख्या में यात्रा करें। उसके लिए दिल्ली सरकार प्रतिबद्ध है। यही कारण है कि दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री की हुई है। क्योंकि जब महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री होगी तो महिलाएं अपने घर से बाहर निकलेंगी। लड़कियां कॉलेज जाएंगी। महिलाएं अपने घर से दूर भी काम की तलाश कर सकती हैं। महिलाएं जितनी ज्यादा से ज्यादा संख्या में घरों से बाहर निकलती हैं, उससे किसी भी अर्थव्यवस्था का विकास होता है। दिल्ली में सभी महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री की गई है और हम प्रतिबद्ध हैं कि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा संख्या में बसों में यात्रा करें।

मुख्यमंत्री आतिशी ने आगे कहा कि हमने दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की तरफ से डीटीसी और कलस्टर की सभी बसों और कंडक्टरों के लिए यह आदेश निकलवाया है और सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर कोई भी महिलाओं के लिए बस नहीं रोकता हुआ पाया गया, अगर कोई भी ऐसा ड्राइवर और कंडक्टर है, जो सिर्फ बस स्टॉप पर महिला यात्री को देखकर बस को तेजी से चलाकर आगे निकल गया और उसने बस नहीं रोकी तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों को सस्पेंड किया जाएगा। मैं दिल्ली की महिलाओं से यह भी निवेदन करूंगी कि अगर आप कहीं भी ऐसा देखती हैं कि बसों को नहीं रोका जा रहा है तो आप बस की फोटो लीजिए। बस के लाइसेंस नंबर की फोटो लीजिए और सोशल मीडिया पर डालिए। सोशल मीडिया पर अगर कोई भी ऐसी शिकायत आती है तो वहां पर जो भी बस का नंबर, ड्राइवर और कंडक्टर है, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ड्राइवर को सस्पेंड किया जाएगा।

भाजपा का डबल इंजन युवाओं पर डबल अत्याचार का प्रतीक बन गया है : प्रियंका गांधी

(एजेन्सी)।

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे प्रदर्शनकाारियों पर बल प्रयोग किए जाने को लेकर सोमवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का डबल इंजन युवाओं पर डबल अत्याचार का प्रतीक बन गया है। बीपीएससी की 13 दिसंबर को हुई परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर पटना में विरोध कर रहे प्रदर्शनकाारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने रविवार को पानी की बौछार की और हल्का बल भी प्रयोग किया। इसके साथ ही जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी के अध्यक्ष समेत 600-700 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, बिहार में तीन दिन के अंदर दूसरी बार छात्रों पर अत्याचार किया गया। परीक्षाओं में भ्रष्टाचार, धांधली, पेपर लीक रोकना सरकार का काम है। लेकिन भ्रष्टाचार रोकने की जगह छात्रों को आवाज उठाने से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस कड़ाके की ठंड में युवाओं पर पानी की बौछार और लाठी चार्ज करना अमानवीय है। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा का डबल इंजन युवाओं पर डबल अत्याचार का प्रतीक बन गया है।

■ संक्षिप्त समाचार

'मनमोहन सिंह को मिलना चाहिए भारत रत्न'

नई दिल्ली (एजेन्सी)। चर्चा के बाद, प्रस्ताव को पार्टी लाइनों से परे सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया, साथ ही विधानसभा ने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि देते हुए दो मिनट का मौन भी रखा। हालाँकि, विपक्ष के नेता के चन्द्रशेखर राव सत्र में शामिल नहीं हुए। रेड्डी ने सिंह की मृत्यु को देश के लिए अपूरणीय क्षति बताया और तेलंगाना की आकांक्षाओं को पूरा करने में उनके नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार उनके योगदान की मान्यता में हैदराबाद के वित्तीय जिले में सिंह की एक प्रतिमा स्थापित करेगी। प्रस्ताव के समर्थन में बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने सिंह को आधुनिक भारत का मूक वास्तुकार" कहा। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि विधानसभा एक अलग प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राष्ट्रीय राजधानी में पूर्व प्रधान मंत्री पीवी नरसिम्हा राव के लिए एक स्मारक स्थापित करने का आग्रह करे। भाजपा के सदन नेता महेश्वर रेड्डी ने शोक प्रस्ताव के लिए अपनी पार्टी का समर्थन व्यक्त किया, लेकिन राहुल गांधी के संबंध में टिप्पणी की, जिसके कारण विधायी मंत्री श्रीधर बाबू ने आपत्ति जताई। मंत्री ने अध्यक्ष से रेड्डी की टिप्पणियों को हटाने का अनुरोध किया।

चमोली में हिमस्खलन के लिए अलर्ट जारी

चमोली (एजेन्सी)। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की प्रयोगशाला रक्षा भूसूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान (डीजीआरई) ने रविवार को अगले 24 घंटों में उत्तराखंड के चमोली जिले में 3,000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर हिमस्खलन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। यह अलर्ट रविवार शाम पांच बजे से सोमवार शाम पांच बजे तक 24 घंटे की अवधि के लिए है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहम्मद ओबैदुल्ला अंसारी ने चमोली के जिलाधिकारी को पत्र लिखकर क्षेत्र के लिए डीजीआरई के ऑरेंज अलर्ट (स्तर तीन) की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने जिलाधिकारी को भेजे पत्र में कहा कि अलर्ट के मद्देनजर उचित सुरक्षा और एहतियाती कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित अधिकारियों को अलर्ट रहना चाहिए। चमोली जिले के 2,500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों में भारी बर्फबारी हुई है, जबकि निचले इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के मीडिया प्रभारी हरीश गौड़ ने बताया कि रविवार को बद्रीनाथ में कई दिनों के बाद सूरज निकला, लेकिन मंदिर में डेढ़ फुट बर्फ जमी हुई है।

छात्रों के आंदोलन को किया हाईजैक, प्रशांत किशोर पर तेजस्वी का आरोप

बिहार (एजेन्सी)। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव ने जन सुराज पार्टी पर परोक्ष हमला बोलते हुए प्रशांत किशोर द्वारा नवगठित पार्टी पर बिहार में नीतीश कुमार के सत्तारूढ़ गठबंधन की 'बी टीम' के रूप में काम करने का आरोप लगाया। हाल ही में बीपीएससी परीक्षा का विरोध कर रहे छात्रों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस द्वारा पानी की बौछारें करने के कुछ घंटों बाद, पूर्व उपमुख्यमंत्री ने एक वीडियो संदेश में कहा कि प्रदर्शनकारियों को गांधी मैदान की ओर मार्च करने के लिए गुमराह किया गया था। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यादव ने आरोप लगाया कि यह आंदोलन छात्रों द्वारा शुरू किया गया था। गर्दनीबाग में लगभग दो सप्ताह तक चले धरने, जहां मैं भी हाल ही में गया था, ने सरकार को हिलाकर रख दिया था। इस समय, कुछ तत्व सरकार की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा करने के खिलाफ प्रशासन की चेतावनी के बावजूद, प्रदर्शनकारियों को गांधी मैदान की ओर मार्च करने के लिए गुमराह किया गया। और, जब लाठीचार्ज और पानी की बौछारों का सामना करने का समय आया, तो जिन लोगों ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने की पेशकश की थी, उन्होंने भागने का फैसला किया। हालाँकि जब पुलिस ने बल प्रयोग किया तो प्रशांत किशोर वहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन रविवार को उन्होंने अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया था। इसके बाद किशोर, जन सुराज पार्टी के अध्यक्ष मनोज भारती और कई अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।

ऑरियनप्रो को दिल्ली मेट्रो के लिए एएफसी गेट, कार्ड रीडर बनाने का मिला ठेका

नई दिल्ली (एजेन्सी)। प्रौद्योगिकी कंपनी ऑरियनप्रो सॉल्यूशंस को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) से स्वचालित किराया संग्रह (एएफसी) प्रौद्योगिकी और विनिर्मित समाधान का ठेका मिला है। कंपनी ने सोमवार को बयान में कहा, इनमें डीएमआरसी के प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण नेटवर्क के विभिन्न परिचालन क्षेत्रों के लिए स्वचालित गेट, वैलिडेटर तथा कार्ड रीडर की आपूर्ति की जाएगी। इसमें कहा गया, इस परियोजना के लिए एएफसी गेट का निर्माण पूरी तरह से ऑरियनप्रो की गाजियाबाद स्थित फैक्टरी में किया जाएगा। कंपनी को चेन्नई मेट्रो के दूसरे चरण के लिए एएफसी प्रणाली देने के लिए चेन्नई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से भी नवंबर 2024 में एक ठेका मिला था।

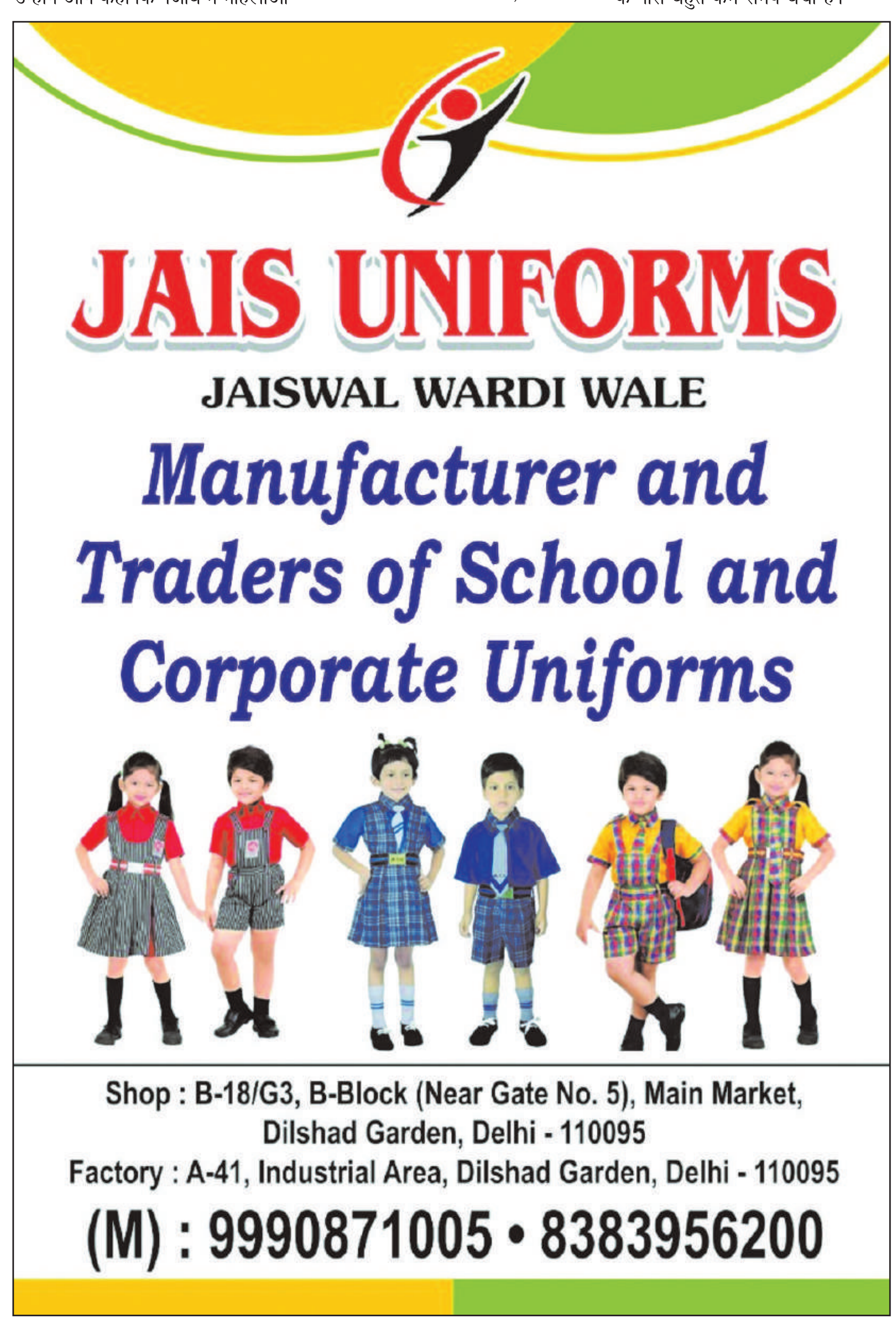

सम्पादकीय

झूठा प्रचार कुछ नहीं होता

मौन को अवगुण कमजोरी की तरह स्थापित किया और इसके सामने बड़बोलेपन को सबसे बड़े गुण की तरह पेश। लेकिन सब तूमार (फेब्रिकेशन) खत्म हो गया। इतना मीडिया, इतना पैसा, पूरी सत्तारूढ़ पार्टी, सरकार सब फेल हो गए। शांति से मौत के आगोश में गए मनमोहन सिंह आखिरी-आखिरी तक कुछ नहीं बोले। मगर उनके जाते ही लोग जिस तरह बोले, मीडिया के मुंह से अनायास सच निकला उसने बता दिया कि झूठा प्रचार कुछ नहीं होता है। किसी सच को हमेशा के लिए दबा कर नहीं रख सकता। काम, शराफत और विद्वता अपने आप बोलते हैं। और फिर झूठ, उपहास, बड़बोलापन उसके सामने बहुत बौने हो जाते हैं। मौन, कम बोलना, केवल आवश्यक बोलना, साधना, विद्वता से अर्जित सबसे विरल गुण होता है। उसे कमजोरी बताया। जो सबसे ताकतवर आन्तरिक शक्ति है उसका उपहास उड़ाया! एक उदाहरण देते हैं। राम का। रामचरित मानस, वाल्मिकी कृत रामायण कहीं ज्यादा बोलते हुए दिखे? कौन था सबसे बड़बोला? सबका उपहास उड़ाने वाला? किसी को कुछ नहीं समझने वाला? नाम बताएं क्या? रावण के अलावा और कौन? महाभारत में सबसे ज्यादा कौन बोलता है? दुर्योधन ही ना! कहीं अर्जुन ज्यादा बोलता दिखा? मगर गजब है हमारा मीडिया। भाजपा की तो ठीक है राजनीति है। और दूसरे की लकीर छोटी करने के अलावा उसके पास कुछ और है भी नहीं। दक्षिणपंथी विचार की यह मजबूरी है। नकारात्मकता से वह निकल ही नहीं पाती है। उसे तो चरित्रहनन करना था। गांधी, नेहरू, आंबेडकर से लेकर मनमोहन सिंह, सबका। मगर मीडिया, देश के दूसरे संस्थान, जनता, बुद्धिजीवी वर्ग सबको क्या हो गया था? 56 इंच की छाती, लाल आंखें करना, एक अकेला सब पर भारी की आत्मश्लाघा को गुण बता रहे थे! और अन्तमुर्खी स्वभाव, नर्म लहजा, शब्दों के उचित चयन को कमजोरी! क्या हुआ? सब भरभरा कर गिर गया। मनमोहन सिंह ने कुछ नहीं किया। 2014 से घर में बैठे थे। जब प्रधानमंत्री मोदी ने गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए कोई मदद मांगी, बिना किसी को बताए, बिना प्रचार किए दी। इसके बावजूद दी कि उनके कुर्सी से हटते ही उनके घर सीबीआई पहुंचा दी थी। क्या हुआ? क्या मिला? गिरफ्तार करना था उन्हें। लेकिन मनमोहन सिंह पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। कोई विद्वेष की भावना नहीं आई। यह बड़प्पन होता है। गुरुता! और इसलिए मीडिया का, भाजपा का, मोदी सरकार का, भक्तों का बांधा हुआ सारा तूमार एक मिनट में खत्म हो गया। मनमोहन सिंह के जाते ही उन्हें दिल से याद करने, आम भारतीयों की जिन्दगी बदलने, देश का भाग्य पलट देने, हर तरफ काम ही काम के मौके देने के किस्से आम-ओ-खास सबके मुंह से निकलने लगे। अंबानी-अडानी जो मोदी सरकार के खास हैं वे भी कह पाए कि मनमोहन सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था डूबी थी थी। बोलना था तो इतना ही बड़ा झूठ बोलना था। मीडिया संभाल लेता। मगर हिम्मत नहीं पड़ी। और उनकी क्या जिन प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें देहाती औरत, रेनकोट पहनकर नहाने वाला और यहां तक कि पाकिस्तान से मिलकर मनमोहन सिंह और कुछ कांग्रेसी नेता गुजरात में उनकी सरकार बदलना चाहते हैं जैसे आरोप लगाए उन्हें भी श्रद्धांजलि देते हुए मनमोहन सिंह के लिए ईमानदार शब्द का उपयोग करना पड़ा। माहौल से बड़ा कोई नहीं होता। मनमोहन सिंह की मौत के बाद अचानक ऐसा माहौल बदला कि कोई उन शब्दों को नहीं बोल सका जो 2004 से जब से वे बने थे उनकी मृत्यु से कुछ समय पहले तक बोल रहे थे। यह सत्य की बहुत बड़ी विजय है। सबने देख लिया कि सच्चाई को हमेशा छुपाया नहीं जा सकता। पूरी दुनिया में तो मनमोहन सिंह को सम्मान मिलता ही था। वहां तो हमेशा से मिलता रहा। इसके बारे में इतना लिखा गया कि सबको मालूम है। यहां फिर से बताने की जरूरत नहीं। मगर यहां जैसा माहौल बदला वह बताना जरूरी है। हालांकि मोदी सरकार ने अपनी राजनीति करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ट्रोल आर्मी, नए भक्त, पुराने भक्त उसको जस्टिफाई करने में लग गए। मगर पहली बार है कि कोई कर नहीं पाया। जनता में सवाल चला गया कि निगम बोध घाट के सार्वजनिक श्मशान घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री की अन्त्येष्टि क्यों? वैसे तो खुद ही करना था। केन्द्र सरकार का काम होता है। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम क्रिया का। लेकिन इस सरकार को जानते थे सब इसलिए मनमोहन सिंह के परिवार ने और कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने सरकार से उनकी अन्त्येष्टि राजघाट क्षेत्र में जहां प्रधानमंत्रियों की समाधियां हैं वहां करने की मांग की थी। मगर सरकार ने निगम बोध घाट निर्धारित किया। वहां क्या हुआ। मनमोहन सिंह के शोक में डूबे परिवार के साथ धक्का मुक्की। पूरी तरह अव्यवस्था। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी देश के नाम संदेश देकर उनके कामों की सराहना कर रहे हैं दूसरी तरफ पूर्ण गरिमा के साथ उनके अन्तिम संस्कार की व्यवस्था भी नहीं।

जयंती

श्रीलाल शुक्ल

जन्म: 31 दिसंबर, 1925; मृत्यु: 28 अक्टूबर, 2011) को लखनऊ जनपद के समकालीन कथा-साहित्य में उद्देश्यपूर्ण व्यंग्य लेखन के लिये विख्यात साहित्यकार माने जाते थे। उन्होंने 1947 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा पास की। 1949 में राज्य सिविल सेवा से नौकरी शुरू की। 1983 में भारतीय प्रशासनिक सेवा से निवृत्त हुए। उनका विधिवत लेखन 1954 से शुरू होता है और इसी के साथ हिंदी गद्य का एक गौरवशाली अध्याय आकार लेने लगता है।

पुण्यतिथि

वी. पी. मेनन

जन्म- 30 सितंबर, 1893, केरल; मृत्यु- 31 दिसंबर, 1965, बेंगळूरू) भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक प्रतिष्ठित अधिकारी थे। भारतीय सिविल सेवा में एक क्लर्क की तरह अपना कॅरियर आरंभ करने वाले मेनन ब्रिटिश भारतीय गवर्नर-जनरल के वैधानिक सलाहकार के पद तक पहुंचे और जब अंतरिम सरकार विफल रही तो मेनन ने ही भारत के विभाजन की सलाह दी। भारत के विभाजन और फिर रियासतों के एकीकरण में वी. पी. मेनन की अहम भूमिका रही। सरदार पटेल के सहयोगी के रूप में भी वह याद किए जाते हैं। हैदराबाद, जूनागढ़ या फिर कश्मीर सबकी कहानी में मेनन का नाम जरूर आता है।

कल मिलेंगे

पिंकी-अरे तू इतनी मोटी कैसे हो गई?
रिंकी-मजबूरी
पिंकी-कैसी मजबूरी?
रिंकी-हमारे घर में फ्रिज नहीं है न
पिंकी-तो?
रिंकी-कुछ बचा नहीं सकते, सब खाना पड़ता है यार...

संजना भारती दैनिक

भगवान शंकर जी के 11वें रुद्रावतार हनुमान जी (मेंहदीपुर, श्री बाला जी) के संरक्षण में संचालित किया जाता है। समाचार पत्र का यह अंक भी उन्हीं के चरणों में श्रद्धापूर्वक समर्पित है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक-**संजय कुमार** द्वारा आर.डी. प्रिंटर एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-41, सेक्टर-8, नोएडा, उत्तर प्रदेश से मुद्रित तथा ए-281सी, गली नं. 3, ए-ब्लॉक, अम्बिका विहार, शिव विहार, दिल्ली-110094 से प्रकाशित। इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत संपादक उत्तरदायी।

RNI No. : DELHIN/2016/70240

Phone No.: 9871221635

E-mail ID: sanjanabharati16@gmail.com

(किसी भी वाद-विवाद में न्याय क्षेत्र दिल्ली ही होगा।)

दूरगामी लाभ का निर्णय है जिलों की समाप्ति का निर्णय

सरकारी ऑफिस, सरकारी बंगले और ना जाने कितने ही कार्यों के लिए स्थान और आधारभूत संरचना विकसित करने के साथ ही अधिकारियों-कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होगी। इसके साथ ही अन्य सुविधाएं और अन्य सेवाएं अलग होगी। हमारे सामने पुराने उदाहरण है जब राजसमंद, प्रतापगढ़, दौसा जिले बनाए गए और करौली व प्रतापगढ़ जिले का गठन किया गया। अब सबके सामने है कि इन जिलों को सही मायने में जिलो का आकार लेने में कितना समय लगा

-डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

राजनीतिक लाभ हानि से जुड़े निर्णयों को बदलना किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिए जोखिम से कम नहीं होता। इस तरह के निर्णय करने में सरकारों को काफी संकोच करना पड़ता है क्योंकि किसी भी निर्णय को बदलते समय राजनीतिक गुणाभाग देखा जाता है और यही कारण है कि कई निर्णय ऐसे होते हैं जिनके लाख चाहने और प्रशासनिक दृष्टि से सही नहीं होने पर भी सरकारें ढोने जाती है। इस मायने में राजस्थान की सरकार की सराहना करनी पड़ेगी कि राजनीतिक दृष्टि से निर्णय लेना मुश्किल व जोखिम भरा होने के बावजूद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पूर्व सरकार के समय के जिले बनाने के निर्णय का परीक्षण कर 9 जिले और 3 संभाग समाप्त करने का निर्णय लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। अब प्रदेश में 41 जिले और 7 संभाग रह गए हैं। दूदू, केकड़ी, शाहपुरा, नीम का थाना, अनूपगढ़, गंगापुरसिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण और सांचौर जिला और बांसवाड़ा, सीकर और पाली संभाग को समाप्त करने का निर्णय ले लिया। निश्चित रुप से शुरूआत में इसका विरोध होगा, राजनीति से जुड़े लोगों द्वारा हवा भी दी जाएगी पर जब कोई दूरगामी जनहित का निर्णय लिया जाता है तो देर सबेर जनता उसे स्वीकार्य भी कर लेती है।

राज्य सरकार द्वारा यही निर्णय नई सरकार बनते ही लिया जाता तो उसके मायने कुछ अलग होते और उस पर राजनीतिक द्वेषता का ठप्पा लगता वह अलग होता। आज भले ही विपक्ष द्वारा इस निर्णय पर प्रश्न उठाये जा रहे हो पर सही मायने में देखा जाए तो यह पूरी तरह से प्रशासनिक निर्णय है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पूर्व सरकार के नए जिले बनाने के निर्णय का परीक्षण करने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी डा. ललित पंवार की अध्यक्षता में समिति गठित कर परीक्षण करवाया और फिर राजनीतिक स्तर पर मंत्रीमण्डलीय समिति बनाकर सभी पक्षों का अध्ययन कर रिपोर्ट आने पर मंत्रीमण्डल की बैठक में मोहर लगाई गई। इसलिए एक बात तो साफ हो जानी चाहिए कि यह निर्णय किसी भी मायने में जल्दबाजी या राजनीतिक लाभ के लिए न होकर पूरी तरह से प्रशासनिक दक्षता के लिए लिया गया निर्णय है। ना ही इसे जल्दबाजी में लिया निर्णय कहा जा सकता है। हालांकि पूर्व सरकार ने नए जिले बनाने के लिए भले ही प्रशासनिक कमेटी बनाकर रिपोर्ट प्राप्त कर नए जिले बनाने का निर्णय किया पर यह सब अच्छी तरह से साफ हो जाना चाहिए कि चुनाव नजदीक होने के कारण पूर्व सरकार द्वारा नए जिले बनाने के निर्णय को आमलोगों ने पूरी तरह से राजनीतिक निर्णय के रुप में ही देखा गया।

भजन लाल शर्मा ने पूर्व सरकार द्वारा गठित नए जिलों के गठन का प्रशासनिक दृष्टि से परीक्षण करवाया और इसमें कोई दो राय नहीं कि शुरूआत में इन जिलों और संभागों को समाप्त करने के निर्णय का विरोध हो पर यह विरोध इसलिए अधिक असर नहीं दिखा पाएगा कि आमनागरिक यह अच्छी तरह से समझता है कि अधिक और छोटे जिले बनने से सरकारी खर्चे अधिक बढ़ने के अलावा कोई खास प्राप्त होने वाला नहीं है। नए जिलों के लिए शुरूआती दौर में ही एक जिले के लिए कम से कम एक हजार करोड़ की व्यवस्था करनी होगी। जिला कलक्टर और जिला पुलिस एसपी के दफ्तर तो तत्काल शुरू करने के साथ ही अन्य विभागों के भी दफ्तर जिला स्तर पर खोलने से ही वास्तविक लाभ प्राप्त हो सकता है। अब इसे यों देखा जाए कि इस सबके लिए कितना बड़ा प्रशासनिक अमला तैयार करना होगा, कितनी अधिक आधारभूत सुविधाएं विकसित करनी होगी।

सरकारी ऑफिस, सरकारी बंगले और ना जाने कितने ही कार्यों के लिए स्थान और आधारभूत संरचना विकसित करने के साथ ही अधिकारियों-कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होगी। इसके साथ ही अन्य सुविधाएं और अन्य सेवाएं अलग होगी। हमारे सामने पुराने उदाहरण है जब राजसमंद, प्रतापगढ़, दौसा जिले बनाए गए और करौली व प्रतापगढ़ जिले का गठन किया गया। अब सबके सामने है कि इन जिलों को सही मायने में जिलो का आकार लेने में कितना समय लगा। आज भी कई स्थानों पर फिजिबल नहीं होने के कारण जिला सहकारी बैंक नहीं खुल पाएं है तो कई अन्य सरकारी दफ्तर शुरू नहीं हो पाये हैं। दरअसल जन हितकारी सरकार की पहचान लोकहित में दूरगामी परिणामों को देखते हुए निर्णय लेना होता है। हालांकि लोकतंत्र में बहुत से निर्णय राजनीतिक प्रतिबद्धता के कारण न चाहते हुए भी लेने होते हैं तो कई बार ऐसा भी लगता है कि ऐन केन प्रकरेण सत्ता में बने रहने के लिए इस तरह के निर्णय ले लिए जाते हैं।

प्रशासनिक दक्षता और लोकहितकारी सरकार की पहचान जनहित में कड़वे निर्णय लेने में भी संकोच नहीं करना होता है। सरकार की संवेदनशीलता और प्रशासनिक दक्षता का भी इसी से पता चलता है। खासतौर से राजनीतिक लाभ हानि से लिए गए निर्णय से अधिक भला नहीं हो पाता है। सरकार की प्रशासनिक और लोकहितकारी होने का इसी से पता चलता है कि वह जनहित में जोखिम भरे निर्णय लेने में भी कोई संकोच ना करें। लोकतंत्र में जनता और जनता का हित बड़ी बात होनी चाहिए क्योंकि सरकार द्वारा निर्णयों का असर दूर तक जाता है। कड़वे निर्णय यदि लोकहित में होते हैं तो जनता ऐसे निर्णयों को हाथोंहाथ लेती है। इसलिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सरकार बनने के पहले साल में ही बड़े निर्णय कर सबको चौंका दिया है। राजनीतिक लाभ हानि से परे हटकर मुख्यमंत्री ने 9 जिले और 3 संभाग समाप्त करने का निर्णय व्यापक जनहित में ही देखा जाना चाहिए।

आर्थिक विश्लेषकों को मानना है कि सरकार को अपने प्रशासनिक खर्चों को एक सीमा तक रखना चाहिए। हालांकि सब कुछ जानते हुए भी होता इसके विपरीत ही है। सरकार राजस्व का अधिकांश खर्चा अपने प्रशासनिक दायित्वों वेतन-सुविधाओं में ही खर्च कर देती है वहीं नए जिले और संभाग बनने से प्रशासनिक खर्च बढ़ना स्वाभाविक है। दूसरी बात यह है कि नए जिले या संभाग बनाने के स्थान पर सरकारों को प्रशासनिक सेवाओं में सुधार और डिलीवरी सिस्टम को मजबूत बनाने पर जोर देना चाहिए।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राजनीतिक जोखिम लेते हुए प्रशासनिक दृष्टि से सराहनीय निर्णय किया है। इससे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और उनकी सरकार ने प्रशासनिक दृष्टि से परिपक्वता का परिचय दिया है। हो सकता है कि निर्णय को लेकर विरोध देखने को मिले पर विरोध के खिलाफ भी सरकार को सख्ती दिखानी होगी इससे आमजन में सरकार और सरकार द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों को सराहा ही जाएगा। सरकारों को राजनीतिक लाभ हानि के साथ ही व्यापक जनहित को भी ध्यान देना चाहिए और निर्णय लेने में किसी तरह का संकोच नहीं करना चाहिये। आज लोग निर्णय लेने वाली सरकार को पसंद करती है नाकि निर्णयों को टालने वाली सरकार को। इस मायने से भजन लाल शर्मा के एक साल के कार्यकाल का भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए क्योंकि यह सरकार निर्णयों की सरकार बन गई है।

प्रधानमंत्रियों के अंतिम संस्कार और स्मारक के लिए अपनाए गए दोहरे मापदंड पर खुद घिरी कांग्रेस

नई दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र में आने वाले कई विधानसभा क्षेत्रों में भी पंजाबी समुदाय की अच्छी संख्या है। जानकार बताते हैं कि पहले कांग्रेस व भाजपा-अकाली गठबंधन में सिख मतों का बंटवारा होता था। लेकिन अब भाजपा व अकाली अलग हो गए हैं जिससे उनका विभाजन संभव है। चूंकि, कांग्रेस की पकड़ भी सिख मतों पर कमजोर हुई है। इसलिए आप को इसका फायदा मिल सकता है

-कमलेश पांडेय

पहले पूर्व प्रधानमंत्री पी वी नरसिम्हाराव और अब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार और उनके स्मारक को लेकर जो घिनौनी राजनीति 'कांग्रेस परिवार' खासकर नेहरू-गांधी परिवार ने शुरू की है, वह बेहद लज्जाजनक और भारतीय राजनीति पर किसी काले धब्बे की मानिंद है। इससे देश का सत्तापक्ष, विपक्ष और जनमानस सभी शर्मसार हुए हैं।

दरअसल, कांग्रेस व विपक्षी दल के कई नेता चाहते थे कि डॉ. मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार राजघाट के पास किया जाए और वहीं पर उनका समाधि स्थल भी बनवाया जाए। जबकि केंद्र सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर किए जाने का फैसला लिया और बाद में उनका स्मारक बनवाए जाने की बात कही। इसी मसले पर सियासत शुरू हो गई।

वहीं, इस मसले पर अबतक हुए सियासी वार-पलटवार में भाजपा से ज्यादा कांग्रेस घिर चुकी है। क्योंकि अब आईना दिखाया जा रहा है कि प्रधानमंत्रियों के अंतिम संस्कार और स्मारक के लिए खुद कांग्रेस के नेतृत्व वाली मनमोहन सरकार ने ही दोहरे मापदंड अपनाए थे। जबकि वह नाहक ही इस मसले पर भाजपा को घेर रही है ताकि फरवरी 2025 में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों में उसे इसका भावनात्मक लाभ मिल सके।

ऐसे में सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या नेहरू-गांधी परिवार के इशारे पर भारत सरकार फैसले लेगी या फिर कोई स्वस्थ परम्परा शुरू करेगी। वहीं, इस मसले पर राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति में भी भेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति भी होता है। बताया गया है कि राजघाट पर स्मारक के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपप्रधानमंत्री और विशिष्ट योगदान देने वाले लोगों की चर्चा तो है, लेकिन उसमें उपराष्ट्रपति का पद शामिल नहीं है। यह हैरतअंगेज है। सवाल है कि पूर्व प्रधानमंत्री पी वी नरसिम्हाराव को मरणोपरांत समुचित पार्टीगत सम्मान व स्मारक हेतु दिल्ली में स्थान नहीं देने का आरोपी 'कांग्रेस परिवार' अब किस मुंह से पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह के लिए मरणोपरांत अंत्येष्टि व स्मारक हेतु राजघाट, दिल्ली में स्थान मांग रहा है और इसे नहीं देने का आरोप 'बीजेपी परिवार' पर लगा रहा है, जबकि एनडीए के नेतृत्व वाले मोदी सरकार की ऐसी कोई नकारात्मक मंशा नहीं है। इस बावत हुए सरकारी पत्राचार और बयानबाजियां इस बात की पुष्टि कर रही हैं।

बता दें कि अपने ही पूर्व प्रधानमंत्री पी वी नरसिम्हाराव को मरणोपरांत समुचित पार्टी स्तरीय सम्मान व स्मारक हेतु दिल्ली में स्थान नहीं देने के लिए जो तत्कालीन मनमोहन सरकार दोषी थी, अब उसी पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह के निधनोपरांत निगमबोध घाट पर हुई उनकी अंत्येष्टि क्रिया करवाए जाने व उनके स्मारक के लिए राजघाट पर अपेक्षित स्थायी जगह नहीं दिए जाने के आरोप मढ़कर कांग्रेस पार्टी भाजपा नीत राजग गठबंधन की मोदी सरकार को दोषी ठहरा रही है। जबकि ऐसा करने से पहले उसे खुद अपने गिरेबां में झांकना चाहिए।

इस मुद्दे पर पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव के भाई मनोहर राव ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस को 20 वर्ष पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि उन्होंने अपने नेता पीवी नरसिंह राव को कितना सम्मान दिया। तब सोनिया गांधी उनके अंतिम संस्कार में शामिल तक नहीं हुई थीं। एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उनके लिए एक भी प्रतिमा का निर्माण नहीं किया या उन्हें भारत रत्न नहीं दिया। हालांकि, आप अपनी औपचारिकताएं पूरी करें, तब बीजेपी निश्चित रूप से डॉ. मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए भूमि देगी।

वहीं, सियासी हद तो यह है कि कांग्रेस इसे अल्पसंख्यक पंजाबी समुदाय विरोधी कृत्य बताते हुए डॉ मनमोहन सिंह का अपमान करार दे रही है, जो पूर्णतया सही नहीं है। इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने से पहले उसे अपने गिरेबां में झांककर देखना चाहिए। उसने अपने ही पूर्व प्रधानमंत्री पी वी नरसिंहराव के साथ जो सुलूक किया, वैसा उदाहरण विरले ही मिलता है।

वहीं, हैरत की बात तो यह भी है कि कांग्रेस द्वारा दिल्ली विधानसभा चुनाव को नजदीक देखकर इस पूरे घटनाक्रम से सिखों को भावनात्मक रूप से जोड़ने का प्रयास किया गया और निगम बोध घाट पर डॉ. मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार को सिखों का अपमान बताया गया। जबकि इससे उसे कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि दिल्ली के सरदार 1984 के सिख विरोधी दंगों को नहीं भूले हैं। इसी की भरपाई के लिए उसने डॉ मनमोहन सिंह को पीएम तक बनाया, लेकिन पंजाबी समुदाय के लोकप्रिय नेता के रूप में वो अपनी छवि नहीं गढ़ सके। क्योंकि कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें कभी फ्री हैंड नहीं दिया! आलम यह है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस को आप और अकाली दल शिरोमणि के नेताओं का भी साथ मिल गया है, जिनका दिल्ली से लेकर पंजाब की सियासत पर अपना वर्चस्व है। इन दोनों दलों ने भी केंद्र सरकार पर सिखों के अपमान का आरोप लगाया है। हालांकि ऐसा सिर्फ इसलिए कि दिल्ली में लगभग 4 प्रतिशत सिख मतदाता हैं, जिसमें राजौरी गार्डन व तिलक नगर जैसे विधानसभा क्षेत्रों में इनकी आबादी 35 प्रतिशत है, जबकि हरि नगर जैसे विधानसभा क्षेत्र में उनकी संख्या 17 प्रतिशत से अधिक है।

वहीं, नई दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र में आने वाले कई विधानसभा क्षेत्रों में भी पंजाबी समुदाय की अच्छी संख्या है। जानकार बताते हैं कि पहले कांग्रेस व भाजपा-अकाली गठबंधन में सिख मतों का बंटवारा होता था। लेकिन अब भाजपा व अकाली अलग हो गए हैं जिससे उनका विभाजन संभव है। चूंकि, कांग्रेस की पकड़ भी सिख मतों पर कमजोर हुई है। इसलिए आप को इसका फायदा मिल सकता है। पिछले दोनों विधानसभा चुनाव व दिल्ली नगर निगम चुनाव में आप को सिखों का अच्छा समर्थन मिला था, लेकिन लोकसभा चुनाव में सिख बहुल क्षेत्रों में भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया है।

इसलिए इन सभी दलों के सामने सिखों को अपने साथ जोड़ने की चुनौती है। जबकि भाजपा ने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली सहित दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कई सदस्यों को अपने साथ जोड़कर सिखों को अपने साथ जोड़ने में लगी हुई है। इससे आप के साथ ही कांग्रेस व अकाली दल परेशान है। तीनों पार्टियों के बीच दिल्ली के साथ ही पंजाब के सिखों को भी अपने साथ जोड़ने की चुनौती है। उल्लेखनीय है कि फरवरी 2025 के पहले सप्ताह में दिल्ली विधानसभा चुनाव है, जिसके चलते भाजपा विरोधी राजनीतिक पार्टियां इसे सिख समुदाय का अपमान बताते हुए इसे मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही हैं। वहीं, भाजपा ने भी इनकी सियासी मानसिकता पर पलटवार किया है, जिसे लेकर राजनीति के और अधिक तेज होने की अटकलें लगाई जा रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस, आप और अकाली दल शिरोमणि के नेता डॉ. मनमोहन सिंह के निधन के अगले दिन से ही बयानबाजी शुरू कर दी है। वहीं, दूसरी तरफ भाजपा भी मुखर होकर कांग्रेस पर घटिया राजनीति करने के आरोप लगा रही है। दुःख के जिस क्षण में कांग्रेस ने इस मुद्दे को सुलगाया, उससे उसका पीवी नरसिम्हाराव वाला जख्म ही जनमानस में हरा हो गया। इससे भाजपा की मोदी सरकार को भी आईना दिखाने का मौका मिल गया।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित कांग्रेस के अन्य बड़े नेता केंद्र सरकार व भाजपा पर सिखों के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि डॉ. मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार और स्मारक के लिए स्थान न ढूंढना भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री का जानबूझकर किया गया अपमान है।

वहीं, गत बृहस्पतिवार को कांग्रेस को आइएनडीआइए से बाहर निकलवाने की धमकी देने वाले आप नेता भी भाजपा विरोधी बयानबाजी में पीछे नहीं हैं। आप सांसद संजय सिंह ने शुक्रवार को प्रेसवार्ता कर मनमोहन सिंह भारत रत्न देने की मांग की। वहीं, निगम बोध घाट पर उनके अंतिम संस्कार के निर्णय को अरविंद केजरीवाल सहित अन्य आप नेता सिख समुदाय का अपमान बता रहे हैं।

खेल/विदेश/कारोबार/फिल्म

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और नवाज शरीफ की आलोचना

(एजेन्सी)।

लाहौर। पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त न करने के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के फैसले की सोशल मीडिया पर कड़ी आलोचना हुई। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चकवाल जिले के गाह गांव में जन्मे सिंह 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनका पिछले बृहस्पतिवार को नयी दिल्ली में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सिंह के निधन पर दुनिया भर से शोक संदेश आए लेकिन न तो शहबाज शरीफ और न ही उनके बड़े भाई और तीन बार प्रधानमंत्री रहे नवाज शरीफ ने उनके निधन पर कोई शब्द कहे। विडंबना यह है कि केवल पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने ही अपनी संवेदना व्यक्त की।

इसके विपरीत, शहबाज शरीफ और पाकिस्तान सरकार के अन्य शीर्ष अधिकारियों ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर के निधन पर संवेदना व्यक्त करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने एक्स पर शोक संदेश जारी किए, जिसे शहबाज शरीफ सरकार ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के सोशल मीडिया पर असहमति के स्वरों को नियंत्रित करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। विल्सन सेंटर साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के निदेशक माइकल कुगेलमैन ने रविवार को एक्स पर कहा, न तो शाहबाज और न ही नवाज शरीफ ने मनमोहन सिंह के निधन पर सार्वजनिक रूप से शोक व्यक्त किया है। इशाक डार की ओर से एक संदेश आया था। फिर भी, यह हैरान करने वाला है। वे समकालीन थे, उनके आर्थिक विचार समान थे और वे भारत-पाकिस्तान संबंधों को बेहतर बनाने की इच्छा रखते थे। उन्होंने आगे कहा: मुझे वास्तव में भारत-पाक संबंधों में अब इतना कुछ दांव पर नहीं लगता, क्योंकि शरीफों को लगता है कि अगर वे मोदी को नाराज करेंगे तो कुछ खो सकते हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि अगर वे सिंह के बारे में कुछ कहते हैं तो मोदी को इससे कोई परेशानी होगी। यह सब थोड़ा अजीब है!

तालिबान ने अफगानिस्तान के सभी एनजीओ को महिलाओं को नौकरी नहीं देने की चेतावनी दी

(एजेन्सी)।

काबुल। तालिबान ने कहा है कि वह अफगानिस्तान में महिलाओं को रोजगार देने वाले सभी राष्ट्रीय और विदेशी गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को बंद कर देगा। तालिबान ने दो साल पहले सभी एनजीओ को अफगान महिलाओं को रोजगार देने से मना किया था, जिसके बाद उसका यह कदम सामने आया है। तालिबान ने यह कदम कथित तौर पर इसलिए उठाया है क्योंकि उसका कहना है कि महिलाएं इस्लामी हिजाब सही तरीके से नहीं पहनती हैं। वित्त मंत्रालय ने चेतावनी दी कि हालिया आदेश का पालन नहीं करने पर ऐसे एनजीओ को अफगानिस्तान में काम करने का लाइसेंस खोना पड़ेगा। मंत्रालय ने कहा कि वह राष्ट्रीय एवं विदेशी संगठनों के पंजीकरण, समन्वय, नेतृत्व और उनकी सभी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जिम्मेदार है। पत्र के अनुसार, सरकार एक बार फिर तालिबान के नियंत्रण से बाहर के संस्थानों में महिलाओं के हर तरह के कामकाज को बंद करने का आदेश देती है। पत्र के अनुसार, सहयोग नहीं मिलने की स्थिति में उस संस्था की सभी गतिविधियां रद्द कर दी जाएंगी और मंत्रालय द्वारा दिया गया संस्था का गतिविधि लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। यह अफगानिस्तान में कार्यरत एनजीओ की गतिविधियों को नियंत्रित करने या उनमें हस्तक्षेप करने का तालिबान का नया प्रयास है।

इस महीने की शुरूआत में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया गया कि अधिक से अधिक संख्या में महिला अफगान मानवीय कार्यकताओं को अपना काम करने से रोका जा रहा है, जबकि राहत कार्य अब भी आवश्यक है।

बुमराह आईसीसी के साल के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर के पुरस्कार की दौड़ में

(एजेन्सी)।

भारत के शीर्ष तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को सोमवार को इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट के साथ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के साल के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर के पुरस्कार के लिए नामित किया गया। इंग्लैंड के एक अन्य बल्लेबाज हैरी ब्रूक और श्रीलंका के कामिंदु मेंडिस को भी इस सूची में जगह मिली है। बुमराह 2024 में टेस्ट क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रहे हैं। उन्होंने 13 मैच में 14.92 की औसत और 30.16 के स्ट्राइक रेट से 71 विकेट चटकाए हैं जो पारंपरिक प्रारूप में किसी भी गेंदबाज का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने मौजूदा बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में भी शानदार प्रदर्शन किया है और चार टेस्ट मैच में 30 विकेट के साथ श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज है।

आईसीसी ने अपनी वेबसाइट पर कहा, 2023 में पीठ की चोट से उबरने के बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी करने वाले बुमराह ने 2024 में गेंदबाजी में अपना दबदबा बनाया। कैलेंडर वर्ष में 13 टेस्ट मैच में बुमराह ने अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 71 विकेट चटकाए और इस प्रारूप में सबसे सफल गेंदबाज रहे। आईसीसी ने कहा, चाहे दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में तेज गेंदबाजों के लिए अनुकूल परिस्थितियां हों या स्वदेश में तेज गेंदबाजों के लिए कठिन परिस्थितियां, बुमराह ने पूरे साल प्रभावशाली प्रदर्शन किया। भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हालांकि इस तेज गेंदबाज ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। आईसीसी ने पर्थ में बुमराह के मैच का रुख बदलने वाले स्पैल को उनके सबसे यादगार प्रदर्शन में से एक माना जिसकी बदौलत भारत ने 295 रन से जीत दर्ज की।

अल्लू अर्जुन के घर पर तोड़फोड़

(एजेन्सी)। तेलुगु फिल्मों के मशहूर अभिनेता अल्लू अर्जुन के आवास पर तोड़फोड़ करने के आरोप में उस्मानिया विश्वविद्यालय-संयुक्त कार्रवाई समिति (ओयू-जेएसी) के गिरफ्तार किए गए तीन सदस्यों ने रविवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि अभिनेता के प्रशंसक उन्हें फोन कर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं। अभिनेता के आवास पर 22 दिसंबर की शाम को छह लोगों ने कथित तौर पर हमला कर फूलों के गमलों को क्षतिग्रस्त कर दिया था और टमाटर फेंके थे। वे फिल्म पुष्पा-2 के प्रदर्शन के दौरान भगदड़ मचने की घटना में जान गंवाने वाली महिला के लिए न्याय की मांग कर रहे थे। ओयू-जेएसी के विभिन्न पदों पर बैठे तीन पदाधिकारियों समेत छह लोगों और कुछ अन्य के खिलाफ तोड़फोड़ का मामला दर्ज किया गया है। छह लोगों को गिरफ्तार किया गया और बाद में स्थानीय अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। घटना के बाद पुलिस ने अभिनेता के आवास पर सुरक्षा भी बढ़ा दी थी। ओयू-जेएसी के तीन सदस्यों ने उस्मानिया विश्वविद्यालय पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया गया है कि अल्लू अर्जुन के प्रशंसक उन्हें फोन कर धमकी दे रहे हैं कि अभिनेता के परिसर में प्रवेश करने पर उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

देश के निर्यात में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ाने की योजना

(एजेन्सी)।

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एनआरआई एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा है कि राज्य सरकार पांच साल की निर्यात नीति लाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि इस नीति का मकसद देश के कुल निर्यात में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत करने का है। साथ ही इससे राज्य को 1,000 अरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिल सकेगी। नई निर्यात नीति 2025-30 के लिए होगी जो मौजूदा पांच वर्षीय नीति की जगह लागू होगी। राज्य सरकार निर्यातकों को राज्य से निर्यात बढ़ाने के लिए कई प्रोत्साहन देने के साथ उनकी हरसंभव मदद भी कर रही है। गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार 2025-30 निर्यात नीति पर काम कर रही है, जिसमें समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए निर्यात क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने ई-मेल के जरिये दिए साक्षात्कार में कहा, नई निर्यात नीति राज्य की हिस्सेदारी को 2023-24 के 4.71 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत करने के लक्ष्य के साथ तैयार की जा रही है। इस नीति का उद्देश्य आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन में तेजी लाना भी है।

गुप्ता ने कहा कि निर्यात क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान देने से उत्तर प्रदेश 1,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा, जिससे राजस्व में वृद्धि होगी तथा विकास को बढ़ावा मिलेगा।

अभी संन्यास का नहीं सोच रहे हैं रोहित शर्मा!

(एजेन्सी)। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट गंवाने के बाद टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की खबरें जोरों पर हैं। मीडिया रिपोर्ट् के मुताबिक रोहित जल्द ही टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। दावा है कि रोहित शर्मा सिडनी टेस्ट के बाद संन्यास ले लेंगे। सिडनी टेस्ट का आगाज 3 जनवरी से होगा। ये मैच अगर पूरे पांच दिनों तक चला तो 7 जनवरी को रोहित शर्मा के टेस्ट करियर का आखिरी दिन हो सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, बीसीसीआई और चयनकर्ता रोहित शर्मा के संन्यास की बातें करने लगे हैं। लेकिन टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा सेलेक्टर्स को मनाने में जुटे हैं। रोहित शर्मा दरअसल, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना चाहते हैं अगर टीम इंडिया पहुंची तो वो मुकाबला उनका आखिरी मैच हो सकता है। वैसे इसकी संभावना कम है ऐसे में सिडनी रोहित का आखिरी टेस्ट मैच हो सकता है। वहीं रोहित शर्मा पर ये रिपोर्ट मेलबर्न टेस्ट में हार के तुरंत बाद आई है। मेलबर्न टेस्ट में टीम इंडिया को 184 रनों से हार का मुंह देखना पड़ा। एक समय ऐसा था जब टीम इंडिया ये टेस्ट ड्रॉ करा सकती थी। टी ब्रेक तक भारतीय टीम के 3 ही विकेट गिरे थे लेकिन इसके बाद ऋषभ पंत एक खराब शॉट खेलकर आउट हो गए और फिर भारतीय पारी धराशाही हो गई। यशस्वी जायसवाल ने 84 रनों की पारी खेली उनके अलावा कोई और बल्लेबाज विकेट पर टिक नहीं पाया। रोहित शर्मा का ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बुरा हाल है। वो इस सीरीज में 3 मैचों में 31 रन ही बना पाए। रोहित का बैटिंग एवरेज 6.20 है। रोहित क्रीज पर टिकने के लिए काफी संघर्ष कर रहे हैं।

हड़ताल न होना सबसे बड़ी उपलब्धि- पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल

■ सेन्ट्रल बार में सम्मान समारोह का हुआ आयोजन

एसबी संवाददाता

वाराणसी। सोमवार को सेन्ट्रल बार एसोसिएशन के गाँधी सभागार में अधिवक्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का उद्धघाटन समारोह के मुख्य अतिथि पुलिस कमिश्नर और आगत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया।

मोहित अग्रवाल और मंचासीन अतिथियों द्वारा सेन्ट्रल बार द्वारा प्रकाशित डाक्यूमेंट्री का विमोचन किया गया। इस अवसर पर मोहित अग्रवाल ने सेन्ट्रल बार के गाँधी सभागार के वातानुकूलित कक्ष का रिमोट कंट्रोल से लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने कहा की वर्ष पर्यन्त बार द्वारा हड़ताल न करना सबसे बड़ी उपलब्धि है। सेन्ट्रल बार और बनारस बार ने न्यायहीत में सराहनीय कार्य किया है। इसके लिए दोनों बार के पदाधिकारी साधुवाद के पात्र हैं।

सम्मान समारोह में सेन्ट्रल बार के प्रबन्ध समिति सहित वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिवक्ताओं का सम्मान माला, शाल और मोमेंट देकर मुख्य अतिथि मोहित अग्रवाल द्वारा किया गया।

समारोह का संचालन सेन्ट्रल बार के महामंत्री सुरेन्द्रनाथ पाण्डेय ने किया तथा अध्यक्षता अध्यक्ष मुरलीधर सिंह ने किया। इस अवसर पर बनारस बार के अध्यक्ष अवधेश सिंह, महामंत्री कमलेश सिंह यादव सहित नवनिर्वाचित अध्यक्ष सेन्ट्रल बार मंगलेश दूबे, महामंत्री राजेश गुप्ता, बनारस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सतीश तिवारी, महामंत्री शशांक श्रीवास्तव, योगेश उपाध्याय, दीपक राय कान्हा, राजेन्द्र त्रिवेदी, गौतम कुमार झा सहित सैकड़ों अधिवक्ता उपस्थित थे।

पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल को सम्मानित करते हुए सेन्ट्रल बार के अध्यक्ष मुरलीधर सिंह और महामंत्री सुरेन्द्रनाथ पाण्डेय। (छायाः एसबी)

सम्मान समारोह में अधिवक्ता गौतम कुमार झा को सम्मानित करते हुए पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल। (छायाः एसबी)

सामयिक रचनाओं से कवियों ने दी 2024 की विदाई

एसबी ब्यूरो प्रमुख/डॉ. संजय

हाजीपुर। ऐतिहासिक गाँधी आश्रम स्थित गाँधी स्मारक पुस्तकालय में रविवार को संध्या पूस मास की कवि-संगोष्ठी आयोजित हुई जिसकी अध्यक्षता डॉ० अशोक कुमार सिंह ने की तथा संचालन डॉ० संजय 'विजित्वर' ने किया। इस अवसर पर कवियों ने अपनी-अपनी सामयिक रचनाओं से 2024 की विदाई दी जिसपर खूब वाहवाही हुईऔर तालियाँ बजी। कवि- संगोष्ठी की शुरूआत वरिष्ठ कवि मणिभूषण प्रसाद सिंह अकेला की बज्जिका रचना - बेटी,बहिना कुहुक रहल हय-- से हुई। इसके बाद वरिष्ठ कवि हरि विलास राय ने - आज धरती पर उतरल हय चॉंद --सुनाई। इस क्रम में वरिष्ठ कवि डॉ० नन्दू दास ने - तेरा दरद न जाने कोय --। डॉ० शिव बालक राय प्रभाकर ने - जनतंत्र की धरती को बार-बार प्रणाम। वरिष्ठ कवि शंभु शरण मिश्र ने बज्जिका रचना - ई जुग में जीयेला हओ तऽ हाथ में लऽ तू तलवार --। युवा कवि उमेश कुमार निराला ने - बीते हुए खेल को भुलाया नहीं जाएगा-- । पूर्व नौसैनिक सोनू कुमार ने - हमने तो घरों से ऑगन छीनते हुए देखा है--। वरिष्ठ कवि सीताराम सिंह ने गेय रचना - यादें चुपके से आती चोरों की तरह--। वीरेन्द्र कुमार सिंह ने - हम बेटी नहीं गाय दे रहे हैं।

वरिष्ठ रंगकर्मी मनोरंजन वर्मा ने - रंगीन सितारों से कुछ बात कहें-- । नन्हा बालक युग ने -हमारी पहचान है कि हम हिन्दुस्तानी हैं। प्रो० अनिल लोदीपुरी ने महाकवि सुमित्रा नंदन पंत की रचना - रश्मि का आना -- की आवृत्ति पाठ किया। कवि-संगोष्ठी का संचालन कर रहे संयोजक, डॉ० संजय 'विजित्वर' ने - नये साल का होगा आगमन, सुस्वागतम, सुस्वागतम -- तथा बज्जिका की -सुन ल कक्का हम्मर बात-- सुनाई। अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ कवि डॉ० अशोक कुमार सिंह ने - जेब में पैसे नहीं इश्क फरमाने का -- । कार्यक्रम के अन्त में धन्यवाद ज्ञापन पूर्व सैनिक सुमन कुमार ने किया। इस अवसर पर डॉ० शैलेन्द्र राकेश, विपिन कुमार सिंह, बाबू साहेब, देवोपमा, निरुपमा, हिमांशु राज, विक्रम कुमार, सुशांत शेखर, मन्नी, संजय कुमार चौधरी तथा रोहित की उपस्थिति रही।

डीएम ने किया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिल्सी का औचक निरीक्षण

एसबी ब्यूरो प्रमुख इंतजार हुसैन

बदायूँ। जिलाधिकारी निधि श्रीवास्तव ने सोमवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिल्सी का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान ओपीडी, आईपीडी कक्ष, महिला वार्ड, एनबीएसयू कक्ष, लैब, दवा वितरण कक्ष, कोल्ड वार्ड व सभागार कक्ष आदि विभिन्न कक्षाओं का निरीक्षण किया तथा साफ सफाई व्यवस्था दवा वितरण व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था आदि विभिन्न बिंदुओं पर निरीक्षण कर सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने वहां डॉक्टर व स्टाफ की उपस्थिति भी जांची।

जिलाधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिल्सी का निरीक्षण के दौरान पाया कि जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्रसूताओं को मिलने वाला भोजन मैन्यू के अनुरूप नहीं था। सोमवार दोपहर मे मैन्यू मे रोटी, मौसमी सब्जी, दाल, चावल, दही/सलाद है जबकि थाली में दाल एवं रोटी ही पायी गयी। जिस पर जिलाधिकारी ने अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की। जिलाधिकारी ने चिकित्सा अधीक्षक को निर्देशित किया कि सम्बन्धित स्वयं सहायता समूह कैन्टीन का सोमवार का भुगतान मैन्यू के अनुसार नहीं किया जाये।

जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रतिदिन मैन्यू के अनुसार खाने की जांच अवश्य की जाये। उन्होंने निर्देशित किया कि चिकित्सा अधीक्षक प्रसूताओं को मिलने वाले भोजन एवं जननी सुरक्षा योजना के संबंध मे सामु.स्वा. केन्द्रों पर मुख्य स्थानों पर वॉल पेन्टिग कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने मरीजों व तीमारदारों से वार्ताकर दी जा रही सेवाओं के संबंध में फीडबैक भी प्राप्त किया। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में आमजन को जागरूक करने के लिए भी कहा ताकि अधिक से अधिक लोग सरकारी सेवाओं का लाभ ले सके। उन्होंने महिला वार्ड के निरीक्षण के दौरान गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी के बाद जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत दी जाने वाली प्रोत्साहन धनराशि समय से उपलब्ध कराने के लिए कहा।

जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, साफ सफाई व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था आदि विभिन्न बिंदुओं पर निरीक्षण किया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने पाया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 30 बेड की आईपीडी है तथा ऑक्युपेंसी रेट 70 प्रतिशत है। उन्होंने निर्देशित किया कि साफ सफाई की समुचित व्यवस्था हो व शौचालय साफ-सुथरे होने चाहिए।

इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ रामेश्वर मिश्रा, एमओआईसी डॉ अरविंद वर्मा सहित अन्य चिकित्सक व स्टाफ आदि मौजूद रहे।

दिनकर साहित्य कला सम्मान से सम्मानित हुए पीएस लाला व शेरपुरी

■ खेल व युवा विभाग के मंत्री सुरेंद्र मेहता ने किया सम्मानित

एसबी ब्यूरो

बेगूसराय। समस्तीपुर जिले के विद्यापतिनगर प्रखंड अंतर्गत मऊ धनेशपुर दक्षिण पंचायत निवासी कवि, लेखक व साहित्यकार पदमाकर सिंह लाला व शेरपुर गांव निवासी वरिष्ठ साहित्यकार व हास्य व्यंग्य के मशहूर कवि सीताराम शेरपुरी को दिनकर साहित्य कला सम्मान से सम्मानित किया गया है।

राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं के जरिए देश दुनिया में लोकप्रिय बेगूसराय स्थित डीपीएस स्कूल, तेघड़ा परिसर में आयोजित राज्यस्तरीय कवि सम्मेलन के दौरान बिहार सरकार में खेल व युवा विभाग के मंत्री सुरेंद्र मेहता ने उक्त लोगों को पाग, अंग वस्त्र, स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। साहित्य जगत में नामचीन तरुण सांस्कृतिक चेतना समिति,बेगूसराय के अध्यक्ष व चर्चित रचनाकार आनंद कुमार जायसवाल तथा आयोजन सचिव व युवा साहित्यकार, लेखक कवि मिन्टू कुमार झा के संयोजन में आयोजित इस सम्मेलन में काव्य जगत के दर्जनों साहित्यकारों, लेखकों, कवि, गजलकारों ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम को यादगार बनाया। वरिष्ठ पत्रकार व युवा कवि, लेखक पदमाकर सिंह लाला तथा वरिष्ठ कवि, लेखक व साहित्यकार सीताराम शेरपुरी को ख्याति लब्ध कवि और साहित्यकार प्रो.सत्यसंघ भारद्वाज, गजलकार रचना लता, वाचस्पति सौरभ रेणु, डा. सच्चिदानंद पाठक, रेखा शर्मा, श्रीराम राय, देवनीति राय, नितीश शेरपुरी, अजीत कुमार झा, उमेश कुंवर आदि लोगों ने शुभकामनाएं दी।

होनहार बिरवान के होत चिकने पात

एसबी ब्यूरो प्रमुख/डॉ. संजय

हाजीपुर। जी हां, सच ही कहा गया है कि 'होनहार बिरवान के होत चिकने पात'-कुछ ऐसी ही बात आठवीं कक्षा में अध्ययनरत छात्र अथर्व आनंद के लिए चरितार्थ हुई है। अथर्व आनंद ने अपनी लगन, हिम्मत और समर्पण की बदौलत छोटी-सी अवस्था में टेनिस के क्षेत्र में एक विशेष पहचान बनाई है। अमित रंजन चौधरी के सुपुत्र अथर्व आनन्द बिहार के बेगुसराय जिला के मूल निवासी हैं और जिन्होंने पटना डॉनबास्को से शिक्षा-दीक्षा के क्रम में आठवीं कक्षा में अध्यनरत रहकर टेनिस जगत में एक मुकाम हासिल की है। बता दें कि उसने अंडर-18 में आल इंडिया एआईटीए चैम्पियनशिप सीरीज-07 टेनिस टूर्नामेंट-2024 जो 23 दिसंबर से 27 दिसंबर 2024 तक बिहार सेक्रेटेरिएट स्पोर्ट्स फाउण्डेशन, पटना द्वारा आयोजित हुई थी उसका क्वार्टर फाइनल सिंगल खेला तथा डबल्स (मेन) में वीनर घोषित हुए हैं। अथर्व आनंद की इस उपलब्धि से परिवार, समाज तथा उनके हितैषियों, शुभचिन्तकों में काफी हर्ष है। उनकी इस उपलब्धि से प्रसन्नता जाहिर करते हुए शुभकामना देनेवाले में हाजीपुर गाँधी आश्रम निवासी हिमांशु राज, सुशांत शेखर, कुमार विकास, राजीव कुमार, प्रशांत सहित कई युवा शामिल हैं।

विधानसभा क्षेत्र में जनसम्पर्क अभियान चलाया गया, लोगों का मिला भरपूर समर्थन

एसबी ब्यूरो

तेघड़ा/बेगूसराय। 143 तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र से समाजसेवी सह एयरफोर्स से अवकाश प्राप्त वरीय पदाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह उर्फ आनंद जी ने सोमवार को विधानसभा क्षेत्र में चकिया, मल्हीपुर, बीहट, बिंदटोली आदि गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाकर मतदाताओं से आशीर्वाद मांगा। उन्होंने कहा कि हम नेता नहीं बेटा बनकर आपकी सेवा करेंगे। वहीं विधानसभा क्षेत्र के लोगों का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। श्री सिंह ने कहा कि 2025 में हम आपके बीच में सेवक बनकर आएंगे। आप लोगों का आशीर्वाद मिला तो सुंदर और आकर्षक विधानसभा क्षेत्र को बनाएंगे। इनके साथ सैकड़ों की संख्या में लोगों का हुजूम देखने को मिला।

वहीं स्थानीय लोगों ने क्षेत्र की समस्या से चंद्रप्रकाश सिंह को अवगत कराया। वहीं उन्होंने कहा कि जल्द ही समस्या से निजात दिलवाएंगे। बताते चलें कि चंद्रप्रकाश सिंह उर्फ आनंद जी ने लगातार समाजिक क्षेत्रों में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।

मौके पर संध्या कुमारी, शंभू सिंह, नत्थू बिहारी, राजा कुमार, मन्नू कुमार, नितीश कुमार, जगधरी बिंद, भोलाकांत बिंद, मिक्कू बिंद, परमेश्वर पासवान, गवनदेव भूरिया, दल्ली पासवान आदि मौजूद थे।

दिनकर साहित्य कला सम्मान-2024 से सम्मानित हुए कवयित्री

एसबी संवाददाता

बेगूसराय। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय के हिन्दी शिक्षिका अर्चना कुमारी को तरुण सांस्कृतिक चेतना समिति, बेगूसराय के तत्वावधान में आयोजित राज्य स्तरीय विराट कवि सम्मेलन में दिनकर साहित्य कला सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान इन्हें साहित्य और संस्कृति में विशिष्ट जागरूकता फैलाने और अनेकानेक साहित्यिक उपलब्धियों के लिए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुरेंद्र मेहता खेल मंत्री, बिहार सरकार के कर कमलों से प्रदान किया गया। कवि सम्मेलन का आयोजन कवि चर्चित साहित्यकार मिन्टू कुमार झा के सयोजकत्व में डी पी एस तेघड़ा में गत रविवार को किया गया। बेगूसराय शिक्षिका का गृह जिला होने के कारण यह सम्मान और विशिष्ट हो जाता है। कवयित्री के साथ समस्तीपुर के और कई नामचीन कवियों को सम्मानित किया जिसमें कवि प्रवीण कुमार चुन्नू, कवि सत्यसंध भारद्वाज, कवि शिव कुमार सिंह, कवयित्री रंजना लता। रेखा शर्मा स्नेहा, विदित हो कि कवयित्री अर्चना कुमारी गत वर्षों में कई राज्यों नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश आदि में हिन्दी भाषा और साहित्य का प्रचार-प्रसार किया।

इस उपलब्धि के लिए शिक्षिका के परिवार जनों के साथ विद्यालय के प्राचार्य, उप प्राचार्य एवम अन्य शिक्षकों के साथ समस्तीपुर के वरिष्ठ कवि प्रो. ब्रह्मदेव कार्य, शिवेंद्र कुमार पांडेय, अशोक कुमार सिन्हा, आचार्य विजय व्रत कंठ कवि कवि शिव कुमार, ज्वाला सांध्यपुष्प, प्रवीण कुमार चुन्नू, लाल बाबू चौधरी, अरविंद कुमार चौधरी, सत्यसंध भारद्वाज, प्रख्यात कवयित्री प्रीति सुमन, रेणु शर्मा, डॉ प्रतिभा परासर आदि ने बधाई दी है।

नए साल पर खुशी मनाने की छूट, लेकिन हुड़दंग बर्दाश्त नहीं: यूपी डीजीपी

(एजेन्सी)।

लखनऊ। 2024 का आखिरी दिन आपका मंगलमय रहे और आप नव वर्ष 2025 का स्वागत कर सकें इसके लिए आपको, उसमें भी खासकर युवाओं को अपने ऊपर कुछ नियंत्रण रखना होगा। नए साल का स्वागत हुड़दंग से करने की जगह आप अपने पूरे साल भर का प्लान तैयार करें, कैसे आपको आगे बढ़ना और अपना लक्ष्य हासिल करना है। लेकिन आप अनियंत्रित हुए और आपकी वजह से किसी को परेशानी हुई तो यूपी पुलिस आपके लिए मुसीबत का सबक बन सकती है। क्योंकि उसके कंधों पर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की सुरक्षा के अलावा कानून व्यवस्था संभाले की भी जिम्मेदारी है। इसीलिए नव वर्ष की पूर्व संध्या पर होने वाले आयोजनों के दौरान हंगामा करने वालों से पुलिस सख्ती से पेश आएगी। इसके लिए पूरे प्रदेश में संवेदनशील स्थान चिन्हित कर लिए गए हैं। इन स्थानों पर डिप्टी एसपी व एएसपी स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात रहेगा।

खासकर शराब पीकर गाड़ी चलाने व हुड़दंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) प्रशांत कुमार ने प्रदेश के सभी पुलिस कमिश्नरों, एसपी, डीआईजी व आईजी को ऐसे निर्देश दिए हैं कि जिलों में होटल, क्लब और मनोरंजन गृहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर जहां नववर्ष के कार्यक्रम होते हो, वहां सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जाये। साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में 31 दिसम्बर को फ्लैग मार्च भी निकाला जाए। महिलाओं की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। पर्याप्त संख्या में महिला पुलिसकर्मियों की डयूटी लगाई जाए। प्रशांत कुमार ने 112 पुलिस सेवा को निर्देश दिए हैं कि नए साल पर अक्सर युवक सड़कों पर बाइक व कार तेज गति से चलाते हैं जिससे दुर्घटना होने की सम्भावना बनी रहती है। इसको देखते हुए शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाए। ब्रेथ एनालाइजर से चेकिंग की जाए। सभी प्रमुख बाजारों व सीमावर्ती स्थानों पर नजर रखी जाए।

डीजीपी ने अपने निर्देश में कहा है कि नववर्ष पर धार्मिक स्थानों पर काफी संख्या में श्रद्धालु आते है। इसलिए इन स्थानों पर ट्रैफिक व्यवस्था के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस बल रहे। प्रमुख मंदिरों पर ड्रोन से भी निगरानी कराई जाए। इन स्थानों पर लगे सीसी कैमरे चेक करा लिए जाए। इसके अलावा सोशल मीडिया की 24 घंटे निगरानी की जाए। इन पर आपत्तिजनक पोस्ट व अफवाह होने पर कार्रवाई की जाए।

सूचना

जिला कैथल से नव वर्ष 2025 के शुभ अवसर पर अपने निजी, संस्थान, विभाग के शुभकामना संदेश, विज्ञापन सामान्य शुल्क पर लगवाने के लिए सम्पर्क करें।

दैनिक संजना भारती समाचार पत्र

जिला ब्यूरो प्रमुख कैथलः निर्मल कुमार

9466309795

छात्रों के समर्थन में चिराग पासवान, लाठीचार्ज से हुए नाराज

(एजेन्सी)।

बिहार। बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं संयुक्त परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर पटना में पिछले कई दिनों से छात्रों का प्रदर्शन जारी है। इसको लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। जहां विपक्ष नीतीश सरकार पर हमलावर है। वहीं, सत्तारूढ़ एनडीए के भीतर भी हलचल देखने को मिल रही है। लोजपा (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इसको लेकर लंबा एक्स पोस्ट लिखा है। चिराग ने कहा कि बिहार के युवाओं और बिहार लोक सेवा आयोग अभ्यर्थियों के मुद्दों को लेकर एनडीए सरकार के प्रमुख सहयोगी होने के नाते मैंने बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से तुरंत हस्तक्षेप करने की अपील की है, जिसके परिणामस्वरूप सरकार की ओर से मुख्य सचिव ने अभ्यर्थियों और छात्रों के साथ संवाद की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

केंद्रीय मंत्री ने आगे लिखा कि जल्द ही इस पहल के सार्थक परिणाम दिखेंगे। यह हमारी सरकार की सकारात्मक सोच और छात्रों के प्रति संवेदनशीलता का परिणाम है। मैं अभ्यर्थियों से भी अपील करता हूं कि वे शांतिपूर्ण और रचनात्मक तरीके से अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखें और किसी भी राजनीतिक व्यक्तियों के बहकावे में आने से बचें। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा पूर्ण रूपेण युवाओं के भविष्य और बिहार के विकास से जुड़ा है, जिसे राजनीति से ऊपर रखकर हल किया जाना चाहिए।

चिराग ने कहा कि हमारी पार्टी हर कदम पर युवाओं के साथ खड़ी है। कुछ राजनीतिक व्यक्ति और दल जो छात्रों को भटकाने का काम कर रहें है, ये गलत है। अपने राजनीतिक लाभ के लिए छात्रों का इस्तेमाल करना कतई उचित नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस मामले को लेकर सजग है, सरकार छात्रों की हर संभव मदद के लिए प्रयासरत है। उन्होंने यह भी कहा कि कल पटना में हुए छात्रों पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन के इस्तेमाल का मैं कभी समर्थक नहीं रहा, पुलिस को संयम बरतना चाहिए। छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे है तो उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से समझा कर उनकी समस्याओं के निदान के लिए प्रयास करना चाहिए, न कि लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल। मैंने मुख्यमंत्री जी से इस बात को भी कहा है कि ऐसे पुलिस अधिकारी जो ऐसे कार्यों में संलिप्त पाए जाते है उनपर भी कानून कार्रवाई की जानी चाहिए।

विधायक योगेंद्र राणा ने पार्षदों व नगर पालिका अधिकारियों की ली बैठक

नगरपालिका में पार्षदों व अधिकारियों की बैठक लेते विधायक योगेन्द्र राणा। (छाया: एसबी)

एसबी ब्यूरो प्रमुख/विजय गर्ग

असंध। विधायक योगेन्द्र राणा ने सोमवार को नगर पालिका कार्यालय में पार्षदों व नगर पालिका अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में हल्के से जुड़े विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित कार्यों को जल्द पूरा करवाया जाए।

बैठक में विधायक योगेन्द्र राणा ने विकास कार्यों, शहर की सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट व नालों की मरम्मत के कार्य मुख्य रहे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जिम्मेदारी के साथ अपने कार्यों का निर्वहन करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि असंध विधानसभा में प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य पर विशेष फोकस किया जाए। सभी कार्यों में तेजी लाई जाए। उन्होंने शहर की सीवरेज समस्या के बारे में अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस समस्या का तत्काल समाधान किया जाए। इसके साथ-साथ शहर में सफाई भी सही तरीके से की जाए। उन्होंने जींद चौक स्थित फुव्वारा चौक के सौंदर्यीकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सालवन रोड पर अधूरे पड़े शॉपिंग कॉम्पलेक्स के कार्यों में तेजी लाकर जल्द पूरा करवाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि शहर में नाइट स्वीपिंग को लेकर टेंडर किया जाए। यदि नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों की संख्या कम है तो उसे भी बढ़ाया जाएगा। बैठक में वार्ड-14 पार्षद प्रतिनिधि विजय गर्ग ने भी अपने वार्ड की समस्याएं विधायक के समक्ष रखीं। बैठक के दौरान पार्षदों ने अपने वार्डों से जुड़ी लिखित डिमांड विधायक को दी। विधायक ने जल्द पार्षदों की सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन भी दिया।

इस मौके पर नगर पालिका सचिव प्रदीप कुमार, एमई अशोक कुमार, चेयरमैन राजेंद्र ढींगड़ा, पार्षद सिमांत शर्मा, मेजर सिंह, राजेंद्र भट्ट, पार्षद प्रतिनिधि विजय गर्ग, नरेंद्र छीन्ना, राजकुमार बंसल, पार्षद ममता गोयल, जगदीश गुप्ता, पूर्व चेयरमैन दीपक छाबडा सहित सभी वार्डों के पार्षद उपस्थित रहें।

अपराध पर अंकुश लगाना होगी पहली प्राथमिकता : महाबीर सिंह

एसबी ब्यूरो प्रमुख/विजय गर्ग

असंध। अपराध पर अंकुश लगाना उनकी पहली प्राथमिकता है। अपराध पर अंकुश लगाने के लिए आमजन पुलिस का सहयोग करें। अपराध को रोकने के लिए पुलिस के साथ-साथ जनता का सहयोग बहुत जरूरी है। पुलिस व जनता के बीच आपसी तालमेल व भाईचारे की भावना होना बहुत जरूरी है। गैर कानूनी कार्य करने वाले असामाजिक तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा।

उपरोक्त विचार नवनियुक्त डीएसपी महाबीर सिंह ने कहें। उन्होंने लोगों से अपील की कि नशे को जड़ से खत्म करने के लिए पुलिस को सहयोग दें। अगर उनकी नजर में कोई नशे का धंधा करता है तो उसकी सूचना पुलिस को दें, सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी नशा तस्कर को बख्शा नहीं जाएगा।

जानकारी देते नवनियुक्त डीएसपी महाबीर सिंह।

सोलर मॉडल गांव के लिए तीन जनवरी तक आवेदन करें ग्राम पंचायत: डीसी प्रीति

'जिला में प्रथम रहने वाली पंचायत को मिलेगा एक करोड़ रुपये का अनुदान'

एसबी संवाददाता

कैथल। डीसी प्रीति ने कहा कि पांच हजार की आबादी वाले गांव सोलर मॉडल गांव प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। जो ग्राम पंचायत इस प्रतियोगिता के तहत अपने गांव को सोलर मॉडल गांव बनाना चाहती है, वह ग्राम पंचायतें तीन जनवरी 2025 तक उपायुक्त कार्यालय/अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय/अधीक्षक अभियन्ता बिजली निगम कार्यालय में आवेदन कर सकती हैं।

प्रतियोगिता अवधि (6 महीने) के बाद, सरकारी एजेंसी प्रत्येक संभावित उम्मीदवार गांव की सीमा के भीतर अक्षय ऊर्जा क्षमता का मूल्यांकन करेगी। जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले सोलर मॉडल ग्राम पंचायत को सरकार की ओर से एक करोड़ रुपये की अनुदान राशि दी जाएगी।

डीसी प्रीति सोमवार को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जिला स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधीक्षक अभियन्ता सोमबीर भालौटिया ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में जिला स्तरीय समिति की बैठक में डीसी द्वारा योजना को हर अंत्योदय लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। इस योजना के तहत अंत्योदय परिवार जिनकी सालाना आय 1.80 लाख से कम है व जिनकी सालाना बिजली खपत 2400 युनिट तक है, वे दो किलोवाट तक का सोलर पैनल लगवाने पर भारत सरकार की ओर से 60 हजार रुपये व हरियाणा सरकार की ओर से 50 हजार रुपये अनुदान यानि कि कुल 1.10 लाख रुपये का अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। जिन परिवारों की सालाना आय तीन लाख रुपये तक है व जिनकी सालाना बिजली खपत 2400 युनिट तक है वो परिवार दो किलोवाट तक का सोलर पैनल लगवाने पर भारत सरकार की ओर से 60 हजार रुपये व हरियाणा सरकार की ओर से 20 हजार रुपये का अनुदान यानि कि कुल 80 हजार रुपये का अनुदान प्राप्त कर सकते हैं।

इसके बाद तीन किलोवाट तक का सोलर पैनल लगवाने पर भारत सरकार की ओर से 78 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इस मौके पर एडीसी दीपक बाबू लाल, चेयरमैन सुरभि गर्ग, एलडीएम एसके नन्दा इत्यादि उपस्थित थे।

शहर में अतिक्रमण नहीं होगा सहन, होगी सख्त कार्यवाही : उत्तम सिंह

एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी

करनाल। उपायुक्त उत्तम सिंह ने कहा कि जिलें में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण सहन नहीं किया जाएगा, अगर कोई व्यक्ति अतिक्रमण करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी, इसके इलावा अगर किसी दूध की डायरी का कोई पशु सडक पर आवारा धूमता हुआ पाया गया तो उस डायरी वालें का चालान किया जाएगा तथा उसका पशु भी उसे नहीं लौटाया जाएगा।

उपायुक्त उत्तम सिंह सोमवार को लघु सचिवालय के सभागार में सडक सुरक्षा समिति की बैठक को संबोधित कर रहें थे। उन्होंने नगर निगम के कार्यकारी अभियंता को कहा कि आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए मुहिम चलाए तथा उनको गऊशालाओं मे सुरक्षित पंहुचाए। उन्होंने कहा कि दिसंबर माह में जो 218 पशुओं को गऊशालाओं मे पहुंचाया गया है उनकी संख्या बढ़ाए तथा संबंधित गऊशालाओं को कहें कि वे पशुओं का नियमानुसार चेकअप करवाते रहें। एनएच के अधिकारियों को कहा कि नेशनल हाईवे पर जितने भी अवैध कट है उन्हें तुरन्त प्रभाव से बंद करें तथा उनकी एक रिर्पोट कार्यालय में भी भेजें। उपायुक्त ने पुलिस विभाग के अधिकारियों को कहा कि जिलें में मोबाइल टीम बनाए जो दिन में विभिन्न जगहों पर जाकर विदाउट सीट बेल्ट और तेज गति से चलाने वाले वाहन चालकों के चालान करें। उन्होंने अधिकारी को यह भी कहा कि जिलें में जहां भी ट्रैफिक लाईट लगी हुई है, उन सभी लाईटों में टाईमर होना चाहिए जो सही काम करें, इस विषय में कोई लापरवाही न हो। उन्होंने आईआरएडो पोर्टल के तहत सडक दुर्घटनाओं को होने वाले हादसों बारे, अवैध कटों को बंद करने बारे, सडकों को दुरुस्त करने, स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत वाहनों की चेकिंग करने, पुलिस व आरटीए विभाग द्वारा यातायात नियमों की अवहेलना किए जाने पर चालानिंग के साथ-साथ अन्य बिंदुओं पर चर्चा करते हुए निर्देश दिए।

राजौंद की टूटी-फूटी सड़के बनी परेशानी

नागरिकों की सरकार व प्रशासन से सड़क मरम्मत की अपील

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

राजौंद। राजौंद की टूटी-फूटी सड़के वाहन चालकों, राहगीरों, नागरिकों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। यह टूटी हुई सडके राजौंद की पहचान बन चुकी है। राजौंद नगर, दिल्ली पटियाला हाईवे पर स्थित है। नगर की टूटी-फूटी सड़कों की खबरें आए दिन मीडिया में लग रही है। लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग कैथल व सरकार लंबी तान कर सोए हुए हैं। मीडिया व जनता की आवाज सरकार व प्रशासन के कानों तक नहीं पहुंच पा रही है।

राजौंद में प्रवेश करने पर इस सड़क पर बने हुए गहरे-गहरे गड्ढे वाहनों को कंडम कर रहे हैं, वहीं दो पहिया वाहन चालक इन गड्ढों में गिरकर घायल हो रहे हैं। गर्मी के मौसम में इन सड़कों पर उड़ती हुई धूल दुकानदारों व राहगीरों के नाक में दम कर देती है। बारिश के दिनों में गड्ढे तालाब का रूप धारण कर लेते हैं। राजौंद नले ऊंचे हैं सड़के नीची है नालों का पानी अवर फल होकर इन सड़कों के गढ्ढों को स्वीमिंगपूल में बदल देता है। जनता पूछ रही है क्या सरकार को राजौद के नागरिकों की याद केवल वोट के समय ही आती है। उनकी सार्वजनिक एवं सामूहिक समस्याओं से सत्तारूढ़ सरकार का कोई वास्ता प्रतीत नहीं हो रहा। सरकार व पीडब्ल्यूडी विभाग राजौंद की सड़कों की सुध नहीं ले रहे हैं। नागरिकों ने आरोप लगाया कि सरकार व विभाग राजौंद की सड़कों से सौतेला व्यवहार कर रहे है। जिसका खामियाजा राजौंद के नागरिक व इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालक पिछले कई वर्षों से भुगत रहे हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग कैथल कानों में तेल डाल करके बैठा हुआ है।

नागरिकों ने बताया कि सड़कों के टूटने की शिकायत 'हरपथ ऐप' पर डालने पर पूर्व के वर्षों में बेहतर काम कर रहा था, अब वह भी दम तोड़कर सफेद हाथी बन चुका है। हरपथ ऐप अब ओपन ही नहीं होता। यदि कभी ओपन हो भी जाए तो शिकायतों पर कोई अमल नहीं होता।

संसदीय व विधानसभा चुनाव से पहले जिला कैथल की सड़कों पर खर्च करने के लिए करोडो रुपए के पैकेज की घोषणा की जाती थी। नागरिक पूछ रहे है वह धन कब खर्च होगा या वह एक चुनावी जुमला था या कागजों में खर्च हो चुका है। नागरिक कुलदीप सिंह, विशाल कुमार, सुल्तान, कुलदीप सिंह, विक्रम सिंह, धर्मेंद्र ने सरकार और प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि राजौंद की सड़कों को दुरुस्त करवाया जाए। ताकि लोग सकुशल इस मार्ग पर आवागमन कर सके।

इन मार्गों से गुजरा मुसिबत को दावत देने जैसा हो गया है। आए दिन इस मार्ग पर वाहनों के एक्सल टूट रहे हैं, ट्रालियों के धूरे टूट जाते हैं। यह बेरहम सडके केवल नेताओं के वाहनों पर दया दृष्टि रखती है। यहां से गुजरने वाले वाहन चालक आए दिन सरकार व प्रशासन को कोस रहे हैं। नागरिकों ने सरकार व प्रशासन से पुन गुहार लगाई है कि इस सड़क की सुध ले। सरकार को पीडब्ल्यूडी विभाग कैथल को अब लंबी नींद से जागना चाहिए। ताकि जनता को राहत की सांस मिल सके।

नियमों का गंभीर उल्लंघन कर संचालित की जा रही स्कूल बसें नहीं चलेंगी सड़कों पर: डीसी प्रीति

आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित जिला प्रशासन की प्राथमिकता

एसबी संवाददाता

कैथल। डीसी प्रीति ने जिला शिक्षा अधिकारी एवं आरटीए सचिव को निर्देश दिए हैं कि नियमों का गंभीर उल्लंघन कर चलाई जा रही स्कूल बसों को सड़कों पर न चलने दिया जाए। स्कूल संचालक सर्दियों की छुट्टियों में बसों के संचालन के संबंधित मापदंडों को पूरा करें। ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े। आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने व सुरक्षित आवागन प्रदान करने के लिए सभी संबंधित विभागों व अधिकारियों के बीच आपसी तालमेल होना बहुत आवश्यक है। जिस विभाग की जो जिम्मेदारी बनती है, उसे समयबद्ध पूरा करें और उससे संबंधित एटीआर समय पर भेजना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही उन्होंने आमजन से भी आग्रह किया कि वे धुंध व कोहरे के चलते सभी सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें।

डीसी प्रीति सोमवार को लघु सचिवालय स्थित सभागार में सड़क सुरक्षा समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। डीसी ने बैठक के दौरान बिंदुवार एजेंडों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि सभी अवैध कटों व ब्लैक स्पॉट की पहचान कर आवश्यक कदम उठाएं। साथ ही अवैध कटों को तुरंत बंद करवाया जाए। डीसी ने अवैध कटों को लेकर एडीसी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिए। इस कमेटी में आरटीए, एक्सईएन बीएंडआर एवं एनएचएआई के अधिकारी शामिल होंगे। जो जिले में वैध कटों की आवश्यकता व अवैध कटों को बंद करने संबंधी रिपोर्ट देंगे। इसके साथ ही सभी नेशनल हाईवे तथा स्टेट हाइवे पर हेल्पलाइन नंबर 112 व 1033 से संबंधित बोर्ड लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत स्कूल बसों की नियमित जांच की जाए।

आरटीए विभाग द्वारा उपायुक्त को अवगत करवाया गया कि इस वर्ष नवंबर महीनें तक 284 हादसे हुए, जिसमें 147 लोगों की मृत्यु हुई। नवंबर महीने की बात करें तो इस वर्ष 29 हादसों में 15 लोगों ने जान गवाई है। वहीं चालानिंग की बात करें तो अक्तूबर माह में पुलिस विभाग द्वारा 3077 चालान किए गए, जिसमें 28 लाख 9 हजार 200 रुपये का जुमार्ना लगाया गया। इसी प्रकार आरटीए विभाग द्वारा 198 वाहनों के चालान किए गए, जिसमें 40 लाख 60 हजार 500 रुपये का जुमार्ना लगाया गया। सुरक्षित वाहन पॉलिसी के तहत 662 बसों की जांच की गई, जिसमें 190 वाहनों के संचालन में नियमों का उल्लंघन पाया गया। इस पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

बैठक में विभिन्न एजेंडों पर चर्चा हुई और संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने सेक्टर 18 हुड्डा में सड़क के बीच में खड़े पेड़ों को हटाने को लेकर वन विभाग को सख्त आदेश दिए। एनएचएआई को सख्त निर्देश दिए कि वे तितरम मोड पुल पर लाइट लगाएं। एनएचएआई के अधिकारियों ने बताया कि इसको लेकर एस्टीमेट मुख्यालय भेजा गया है। एजेंडा में नेशनल हाइवे चंदाना टी प्वाइंट के पास ब्लैक स्पॉट बनाने की मांग आई, जिस पर डीसी ने एडीसी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने के निर्देश दिए। वहीं नगर परिषद के अधिकारियों को निर्देश दिए कि बेसहारा पशुओं को गोशालाओं में भेजने के कार्य में तेजी लाएं। इसी प्रकार सिविल सर्जन को सभी प्राइवेट बसों तथा स्कूल बसों के ड्राइवरों की आंखों की जांच करवाने के निर्देश दिए।

जिला स्तरीय एनकॉर्ड की मासिक बैठक का आयोजन

एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी

करनाल। उपायुक्त उत्तम सिंह ने कहा कि नशा समाज के लिए एक गंभीर समस्या है। जिला में नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए स्कूल व कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है इसके साथ-साथ ड्रग केमिस्ट की दुकानों पर भी प्रशासन की पैनी नजर है। इसके अतिरिक्त शिक्षण संस्थाओं के अध्यापक व प्रोफेसर नशे से ग्रसित विद्यार्थियों की पहचान करेंगे और नशा ग्रस्त पाए जाने वाले विद्यार्थियों को परामर्श देना सुनिश्चित करेंगे तथा बच्चों की पहचान गोपनीय रखी जाए।

उपायुक्त उत्तम सिंह शुक्रवार को लघु सचिवालय के सभागार में जिला स्तरीय एनकॉर्ड की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नशा जैसी सामाजिक बुराई से छुटकारा पाने के लिए सभी का समन्वय आवश्यक है। इसलिए सभी विभाग नशे की रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाए व जिन युवाओं को नशे की लत लग चुकी है, उन्हें नशा छुड़वाने के लिए जागरूक करें ताकि नशा मुक्त समाज का निर्माण हो सके। उन्होंने स्पष्ट किया किया कि जागरूकता कार्यक्रम के धरातल पर परिणाम नजर आने चाहिए। उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि शैक्षणिक संस्थानों के नजदीक दुकानों, क्लबों और आहातों में जांच की जाए और नशा पाए जाने पर उनके खिलाफ उचित कार्यवाही की जाए।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नशा-मुक्ति कार्यक्रमों व जागरूकता अभियानों में ग्राम पंचायतों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए और जागरूकता कार्यक्रम निरंतर जारी रखें। बैठक में उपायुक्त ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि धाकड़ कार्यक्रम के तहत जिले में संचालित सभी शैक्षणिक संस्थानों में नशे की रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजन किया जाए और स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के समय समय पर बैग चेक किए जाएं।

अगर किसी बच्चे के पास कोई नशीला पदार्थ पाया जाता है तो इसकी सूचना उसके माता-पिता को दें व उस बच्चे को उचित काउंसलिंग दिलवाई जाए। उन्होंने कहा कि स्कूल व कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी लगातार गैर-हाजिर रहते है तब ऐसे बच्चों पर शिक्षक कड़ी नजर रखें और इसकी सूचना उनके अभिभावकों को भी दें।

एजेंसी प्रतिनिधियों को दिए निर्देश-प्री-सीओडी वेस्ट की एक माह में करें प्रोसेसिंग, पृथक्करण कचरा करें एकत्रित: डॉ. वैशाली शर्मा

एसबी विशेष संवाददाता

करनाल। स्वच्छता रैंकिंग में करनाल को देश के शीर्ष स्वच्छ शहरों में लाने के लक्ष्य तथा ठोस अपशिष्ट के निस्तारण को लेकर नगर निगम आयुक्त एक्शन मोड में काम कर रहे हैं। सोमवार को कलस्टर हैड एवं नगर निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने इस विषय को लेकर करनाल कलस्टर की मासिक समीक्षा बैठक कर नगर निगम व नगर पालिका अधिकारियों तथा सुगम स्वच्छता एजेंसी को निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि कूड़ा मुक्त शहर की रेटिंग को लेकर इस बार 5 स्टार रेटिंग तथा वाटर प्लस हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने निर्देश दिए कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के सभी पैरामीटर्स पर बारिकी से काम किया जाए, कोई भी बिन्दू छूटना नहीं चाहिए।

शहर की सफाई हो सवोच्च प्राथमिकता- उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर की साफ-सफाई को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा जाए। उन्होंने निगम अधिकारियों तथा नगर पालिका सचिवों से कहा कि कार्यालय आते समय शहर की साफ-सफाई को चेक किया जाए। इसके लिए शहरवासियों से भी बात की जाए, कोई समस्या सामने आए तो उसका समाधान करवाया जाए। उन्होंने कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर से बेहतर किया जाए।

कूड़े को पृथक्करण करने पर दिया जोर- हर घर से गीला और सूखा कूड़ा अलग-अलग एकत्र किया जाए, आज की समीक्षा बैठक में निगमायुक्त ने फिर से जोर दिया गया। उन्होंने एजेंसी प्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि वह अपनी एक्सपर्ट टीम को फील्ड में रखें, ताकि नागरिकों को अलग-अलग कूड़ा देने के लिए लगातार जागरूक करते रहें। उन्होंने नगर निगम के मोटीवेटरों को भी निर्देश दिए कि वह शहर में विभिन्न जागरूकता गतिविधियां चलाएं। उन्होंने कहा कि इस कार्य को एक मुहिम में लेकर किया जाए, तभी सार्थक परिणाम सामने आएंगे। प्लांट में मेरठ रोड के साथ लगते क्षेत्र में पेड़-पौधे लगाने के भी निर्देश दिए, ताकि प्लांट में हरियाली बनी रहे और आने-जाने वाले लोगों को गंदगी दिखाई न दें।

कूड़ा उठान को लेकर टोल फ्री नम्बर पर कर सकते हैं शिकायत- समीक्षा के दौरान उन्होंने जानकारी दी गई कि कूड़ा उठाने को लेकर नागरिक को कोई शिकायत है, तो वह उक्त एजेंसी के टोल फ्री नम्बर- 1800 891 1863 के साथ-साथ नगर निगम के टोल फ्री नम्बर-1800 180 2700 पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त नागरिक, स्वच्छ हरियाणा एप व स्वच्छता एप पर भी ऑनलाईन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

कार्यकारी अभियंता करें निगरानी- निगमायुक्त ने कार्यकारी अभियंता प्रियंका सैनी को निर्देश दिए कि ठोस अपशिष्टद्द प्रबंधन संयंत्र पर होने वाली कूड़ा निस्तारण प्रक्रिया पर निरंतर अपनी निगरानी बनाकर रखें। उन्होंने इसके लिए रोजाना आने वाले कूड़े-कचरे की प्रोसेसिंग, बायो कल्चर स्प्रे, विंड रो तथा सीसीटीवी कैमरा की मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने इन बिन्दूओं की रोजाना रिपोर्ट लेने के भी निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त वहां कार्यरत कर्मचारी सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, इसका भी ध्यान रखा जाए। इसके लिए उन्होंने एजेंसी प्रतिनिधियों को भी निर्देश दिए।

प्री-सीओडी वेस्ट की एक माह में करें प्रोसेसिंग- उन्होंने बैठक के हवाले से बताया कि प्री-सीओडी वेस्ट यानि एजेंसी को वंर्क ऑर्डर जारी होने के बाद और ठोस अपशिष्टद्द प्रबंधन संयंत्र के वाणिज्यिक संचालन की तिथि के दौरान करीब 45 हजार मीट्रिक टन कचरा प्लांट पर एकत्रित हो गया था। इसमें से करीब 35 हजार मीट्रिक टन कचरे की प्रोसेसिंग पूरी हो चुकी है।

खेल व शिक्षा के क्षेत्र में अपनी ऊर्जा लगाएं विद्यार्थी: एसपी राजेश कालिया

विद्यार्थियों व आमजन ने लोटे में नमक डालकर नशा ना करने की ली शपथ

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

कैथल। कैथल पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिला पुलिस युवाओं को नशे से दूर रखने तथा खेलों से जोड़ने के लिए खेल गतिविधियों के माध्यम से युवाओं को प्रोत्साहित कर रही है। अभियान के माध्यम से पुलिस का उद्देश्य आमजन को नशे की बुराइयों से अवगत करवाना तथा नशे के आदी युवाओं को समाज की मुख्यधारा में जोड़ना है।

जानकारी देते हुए एसपी राजेश कालिया ने बताया कि नशा एक ऐसी बुराई है जिससे व्यक्ति का अनमोल जीवन समय से पहले ही मौत का शिकार हो जाता है। नशा करने वाला व्यक्ति अपने साथ-साथ पूरे परिवार का जीवन खराब कर देता है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले युवा पीढ़ी को नशे से बचाना होगा। इस अभियान से पहले भी जिला पुलिस की टीम सुबह और शाम युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़कर उन्हें नशे से दूर रहने का संदेश दे रही हैं। इस अभियान से जहां युवा खेलों से जुड़ेंगे वहीं आपराधिक गतिविधियों से दूर रहेंगे। पुलिस प्रशासन के इस अभियान के सार्थक परिणाम सामने आ रहे है तथा जिला के अनेक युवा खेलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं।

पुलिस का उद्देश्य नशे के आदी युवाओं को समाज की मुख्यधारा में जोड़ने का है। अभियान के तहत नशा जागरूकता टीम में शामिल पीएसआई रामलाल, एएसआई ओमप्रकाश, एचसी सुनील कुमार तथा होमगार्ड शमशेर सिंह की टीम द्वारा कैथल में कमेटी चौक स्थित सरकारी स्कूल, ट्रक यूनियन, लेबर चौक, जाखौली अड्डा कैथल, गांव टयौंठा, मोहना, खेड़ी सिकंदर व जांबा में विद्यार्थियों, युवाओं व आमजन को नशे से दूर रहने तथा खेलों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान विद्यार्थियों व आमजन ने लोटे में नमक डालकर नशा ना करने की शपथ भी ली गई। पुलिस टीम द्वारा कहा गया कि नशा मुक्त भारत अभियान में अपना योगदान दें, साथ ही उन्होंने अपील की है कि नशे का कारोबार करने वालों की सूचना डायल 112 पर पुलिस विभाग को दें। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाऐगा।

आवश्यक सूचना

तेजी से बढते राष्ट्रीय हिंदी दैनिक समाचार पत्र, **'संजना भारती'** को चंडीगढ़, पंचकुला सहित पूरा हरियाणा, पंजाब में जिला स्तर, तहसील स्तर, खंड स्तर पर पत्रकार/कोर्सपोंडेट/ प्रतिनिधि, जिला प्रभारी की जरूरत है।

संजना भारती समाचार पत्र, RNI Registered है।

भारत सरकार व हरियाणा सरकार के पैनल पर है।

मीडिया में काम करने वाले, अनुभवी को प्राथमिकता दी जाएगी।

चयनित आवेदकों को आई कार्ड व प्रमीशन पत्र/

DIPRO लैटर जारी किया जाएगा।

इच्छुक आवेदक

फोटो सहित कम्पलीट बायोडाटा/आवेदन

चीफ सम्पादक: दैनिक संजना भारती, समाचार पत्र नई दिल्ली के नाम पर **कार्यालय वाटसेप नम्बर: 94663-09795 पर भेजें।**